सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534

डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 311 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, मंगलवार 25 अगस्त 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

छत्तीसगढ़ के 160 पंचायतों में तैयार किए गए 'जीवामृत मॉडल फार्म'

रायपुर। राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर किसानों को जागरूक कर रही है। कृषि विभाग द्वारा समय-समय पर जैविक खेती के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गौरेला-पेण्ड्रा-मारवाही जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिले की कुल 171 पंचायतों में से अब तक 160 पंचायतों में जीवामृत के उपयोग से मॉडल किसान फार्म तैयार किए गए हैं, जिनका आसपास एवं अन्य गांवों के किसानों को जैविक खेती के लाभों से अवगत कराया जा रहा है। गौरेला विकासखंड में जीवामृत के उपयोग एवं जैविक खेती पर व्यावहारिक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में कृषि विभाग के अधिकारियों एवं विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों ने भाग लिया। किसानों को जीवामृत, मृदा परीक्षण, मिट्टी की गुणवत्ता सुधार, जैविक खेती तथा उन्नत कृषि पद्धतियों की जानकारी दी गई। किसानों को गौरेला के कृषक श्री बृजलाल राठौर के फार्म का भ्रमण भी कराया गया, जहां म्यूटेंट विष्णुभोग धान की फसल में जीवामृत का उपयोग किया गया है। मात्र 22 दिन की फसल में सुगंध आने के साथ ही फसल की बेहतर वृद्धि देखी गई तथा कीट एवं बीमारी का प्रकोप नहीं पाया गया।

सात साल बाद भारत के दौरे पर आ सकते हैं शी जिनपिंगः 400 लोगों का काफिला होगा साथ

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीब 400 अधिकारियों के बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आने की संभावना जताई गई है। हालांकि उनके आने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार चीनी अधिकारी होटल और सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। सात साल बाद शी की संभावित भारत यात्रा 2020 की सीमा झड़पों के बाद दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की कोशिशों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले एक भारतीय सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि चीनी अधिकारी भारत यात्रा को लेकर होटल और सुरक्षा प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।

छत्तीसगढ़ में यूसीसी कवायद तेजः रायपुर में 27 अगस्त को 200 से ज्यादा विशेषज्ञ करेंगे मंथन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) लागू करने की कवायद तेज हो गई है। साय सरकार ने इसकी घोषणा के बाद इसे लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई है। सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की उपस्थिति में 27 अगस्त 2026 को राजधानी के कन्वेंशन हॉल, न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन, रायपुर में एक राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें यूसीसी पर मंथन किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर व्यापक विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से 200 से ज्यादा विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे जो इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे।

प्रमुखों को किया गया आमंत्रित

इनमें आयोग, निगम, मंडल, विभिन्न सामाजिक संगठनों, समाज प्रमुखों, विकास प्राधिकरणों के प्रदाधिकारियों, प्रबुद्ध नागरिक, जनप्रतिनिधि और विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों के विचार, अनुभव और सुझाव कानून के भावी स्वरूप को गढ़ने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

पहलुओं पर होगी चर्चा

बैठक में समान नागरिक संहिता के विभिन्न प्रावधानों, सामाजिक प्रभावों और व्यावहारिक पहलुओं पर गहराई से चर्चा की जाएगी। राज्य शासन का उद्देश्य एक ऐसा समावेशी और संतुलित प्रारूप तैयार करना है जो राज्य के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रख सके। विस्तृत चर्चा/सुझाव हेतु विभिन्न समूह को पृथक से भी आमंत्रित किया जाएगा, समान नागरिक संहिता (niform Civil Code - UCC) का ऑनलाइन सुझाव इस पर भी दिया जा सकता है।

यूपीआई के 10 सालः नकद की टेंशन खत्म मोबाइल में बैंक, क्यूआर ने बदला पेमेंटमोड

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स प्लेटफार्म से पूछा लोगों का अनुभव

नईदिल्ली ए.। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के 10 साल पूरे होने पर इसे भारत के डिजिटल भुगतान के सफर में एक बड़ा मोड़ बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले लोगों से अपने अनुभव साझा करने की अपील की और पूछा कि इस डिजिटल भुगतान प्रणाली ने उनकी जिंदगी को किस तरह आसान बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दशक पहले शुरू हुआ यूपीआई आज जिस स्तर तक पहुंच चुका है, उसकी व्यापकता और पहुंच हर भारतीय के लिए गर्व की बात है।

यूपीआई को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफइंडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में 25 अगस्त 2016 को लॉन्च किया था। हालांकि, इससे पहले अप्रैल 2016 में 21 सदस्य बैंकों

के साथ इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका था। अगस्त 2016 में इसे आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया। उस समय यूपीआई से जुड़े बैंकों ने अपने यूपीआई-सक्षम मोबाइल एप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर पर जारी किए थे। इसके कुछ महीने बाद दिसंबर 2016 में BHIM ऐप लॉन्च किया गया, जिसने आम लोगों के बीच यूपीआई आधारित भुगतान को और आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

10 साल में लेनदेन का आंकड़ा 13 हजार गुना बढ़ा

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, यूपीआई के जरिए होने वाले सालाना लेनदेन में पिछले एक दशक के दौरान जबरदस्त वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2016-17 में यूपीआई के जरिए महज 1.78 करोड़ लेनदेन हुए थे। यह संख्या वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई। यानी एक दशक के भीतर लेनदेन की संख्या में करीब 13,000 गुना की वृद्धि हुई है। यह आंकड़ा बताता है कि यूपीआई किस तेजी से भारत में रोजमर्रा के भुगतान का अहम हिस्सा बन गया है। यूपीआई के विस्तार के साथ सरकार ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में भी बदलाव किए जिससे लोगों को भुगतान करने में आसानी हो रही है।

11 देशों तक पहुंचा भारत का यूपीआई

भारत में लोकप्रिय होने के बाद यूपीआई की पहुंच अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ रही है। वर्तमान में 11 देशों में यूपीआई को स्वीकार किया जाता है। ग्रीस और मालदीव भारत के रियल-टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म को अपनाने वाले सबसे नए देशों में शामिल हैं। यूपीआई का अंतरराष्ट्रीय विस्तार भारत के डिजिटल भुगतान मॉडल की वैश्विक स्वीकार्यता को भी दर्शाता है। इससे विदेशों में भारतीय यात्रियों के लिए भुगतान करना आसान हो गया। यूपीआई एक रियल-टाइम भुगतान प्रणाली है, जिसके जरिए उपयोगकर्ता किसी भागीदार बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के एक ही मोबाइल ऐप से कई बैंक खातों को संचालित कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ में 'लइका चिन्हारी' एप से होगी ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूल से ड्रॉपआउट बच्चों (स्कूल छोड़ चुके बच्चों) को फिर से शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। शाला अप्रवेशी, शाला त्यागी और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा ने 'लइका चिन्हारी' मोबाइल एप तैयार कराया है। इसके जरिए मैदानी स्तर पर घर-घर सर्वे कर बच्चों का डिजिटल रिकार्ड बनाया जाएगा।

सर्वे के बाद चिन्हांकित बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने के साथ उनकी पढ़ाई जारी रखने की भी निगरानी की जाएगी। विभाग का उद्देश्य केवल ऐसे बच्चों को तलाशना नहीं, बल्कि उन्हें दोबारा स्कूल से जोड़कर शिक्षा में बनाए रखना है।

छत्तीसगढ़ में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर करीब 13.8 प्रतिशत बताई गई है। इसे देखते हुए विभाग ने सर्वे और बच्चों के स्कूल में पुनः प्रवेश पर विशेष ध्यान दिया है। सर्वे कार्य के लिए स्थानीय स्तर पर साक्षरता प्रेरकों और अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

एप पर रजिस्ट्रेशन, संकुल समन्वयक करेंगे सत्यापन

चयनित सर्वेकर्ता अपने एंड्राइड मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से 'लइका चिन्हारी' एप डाउनलोड करेंगे। एप में नाम, मोबाइल नंबर, बसाहट, स्कूल सहित जरूरी जानकारी दर्ज कर स्वयं रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद संबंधित संकुल समन्वयक अपनी संकुल ड्डष्ठ से सर्वेकर्ता के चयन और पात्रता का ऑनलाइन सत्यापन करेंगे। सत्यापन के बाद ही प्रोत्साहन राशि की पात्रता मिलेगी।

टीएमसी के 20 बागी सांसदों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

■ सांसद अभिषेक की याचिका पर स्पीकर से मांगा जवाब

नईदिल्ली ए.। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 20 बागी सांसदों की अयोग्यता से जुड़े मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों से जवाब मांगा है। यह मामला पार्टी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की उस याचिका से जुड़ा है, जिसमें इन सांसदों की अयोग्यता से संबंधित याचिकाओं पर फैसला लेने में हो रही देरी को चुनौती दी गई है।

अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उनके समक्ष लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया जाए। लोकसभा अध्यक्ष और सदन के महासचिव की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष से निर्देश प्राप्त करने को कहा है।

तृणमूल कांग्रेस में बगावत के बाद 20 सांसदों ने पार्टी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफइंडिया (एनसीपीआई) में विलय का दावा किया था। इन सांसदों ने लोकसभा में अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग भी की थी। टीएमसी का कहना है कि ये सभी सांसद पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे।

दिल्ली में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामले, अलर्ट मोड पर सरकार

नईदिल्ली ए.। दिल्ली में स्वाइन फ्लू (एच1एन1) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस साल दिल्ली में इन्फ्लुएंजा-ए के 2,300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें शुक्रवार तक एच1एन1 के 1,777 से अधिक मामले शामिल हैं। वहीं, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, अकेले गुरुवार को 114 नए एच1एन1 मरीज मिले। वहीं, स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ने के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में मौजूदा

हालात की समीक्षा और रोकथाम व नियंत्रण के उपायों पर चर्चा हो रही है।

सरकार ने लोगों से अपील की है कि स्वच्छता का ध्यान रखें, भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचें, खांसते-छींकते समय मुंह-नाक ढकें, साबुन से हाथ धोएं और जरूरत पड़ने पर मास्क पहनें। अस्पतालों में पर्याप्त बेड, डॉक्टर, दवाएं उपलब्ध हैं। 35 अस्पतालों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है। दिल्ली में इन्फ्लुएंजा-ए के कुल मामले लगभग 2,392 हैं, जिनमें एच1एन1 प्रमुख है। इन्फ्लुएंजा ए+बी के कुल मामले लगभग 2,602 हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले दिए गए आंकड़ों के अनुसार एच1एन1 के लगभग 1,777 से अधिक मामले दर्ज हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा - हिजाब इस्लामिक आस्था का जरूरी हिस्सा नही

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में यूनिफार्म के साथ हिजाब (हेड स्कार्फ) पहनकर प्रवेश की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों की भी यही राय रही है कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जिसके बिना वह अपने धर्म से बाहर हो जाएं।

हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक किसी शैक्षणिक संस्थान की यूनिफार्म नीति निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण और अनुशासन बनाए रखने के लिए लागू की गई है, तब तक संस्थान के ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर व न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने दिया है।

याची छात्रा ने प्रयागराज के अतरसुइया स्थित एक स्कूल में कक्षा 11 में दाखिला लेते समय यूनिफार्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। छात्रा का कहना था कि वह कक्षा 6 से 10 तक इसी स्कूल में हिजाब पहनकर पढ़ती रही है। याचिका में कहा गया था कि हिजाब पहनना उसके धार्मिक अधिकार, निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत संरक्षित है।

पासबुक में एंट्री लेकिन खाते से रकम गायब, एसबीआई कियोस्क संचालक 1 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी कर फरार

धमतरी। जिले के ग्राम कोर्रा में एसबीआई के कियोस्क सेंटर से ग्राहकों की रकम में कथित हेराफेरी का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार कियोस्क सेंटर संचालक केशव साहू पर करीब 1 करोड़ 75 हजार रुपए की राशि में गड़बड़ी करने का आरोप है। मामला सामने आने के बाद से संचालक फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

भखारा थाना क्षेत्र के ग्राम कोर्रा में एसबीआई से जुड़े कियोस्क सेंटर का संचालन करने वाले केशव साहू पर आरोप है कि

वह ग्राहकों से नकद राशि जमा करवाता था लेकिन उसे उनके बैंक खातों में जमा नहीं करता था। ग्राहकों को भरोसा दिलाने के लिए उनकी पासबुक में पेन से जमा राशि की एंट्री कर दी जाती थी। जब कुछ ग्राहकों ने अपने खातों में जमा रकम की जांच की तो उन्हें पता चला कि पासबुक में दर्ज राशि बैंक खाते में जमा ही नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की। शिकायत के बीच ही कियोस्क संचालक के फरार होने की जानकारी सामने आई।

एएसपी धमतरी डीसी पटेल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में करीब 1 करोड़ 75 हजार रुपए की ठगी सामने आई है। आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश के लिए पुलिस की टीम लगाई गई है।

आरईआरसीटीसी में बड़े बदलाव : अब तेज होगी टिकट बुकिंग, अपग्रेड पर 150 करोड़ खर्च

नईदिल्ली ए.। आईआरसीटीसी पर अब टिकट बुकिंग तेज होगी। प्रबंधन के मुताबिक सिस्टम अपग्रेड होने के बाद सर्वर क्रैश की परेशानी कम होगी। नए बदलावों के बाद रेलवे यात्री बेरोकटोक टिकट बुकिंग कर सकेंगे।तत्काल जैसे पीक समय में आईआरसीटीसी की एप या साइट से टिकट बुकिंग के वक्त पॉइंटर गोल-गोल नहीं घूमेगा।

आईआरसीटीसी के मुताबिक सिस्टम में एक बड़ा अपग्रेड किया गया है जिससे सर्वर क्रैश की परेशानी का सामना नहीं करना होगा और अब व्यस्ततम समय में भी तेजी से टिकट बुकिंग चालू

रहेगी। आईआरसीटीसी के मुताबिक, मौजूदा नेक्सट जनरेशन ई टिकटिंग प्लेटफॉर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा।

एक सर्वर बैठेगा तो दूसरा संभालेगा

रेलवे सिर्फ सिस्टम की क्षमता बढ़ाने तक सीमित नहीं है। आईआरसीटीसी एक सक्रिय रिकवरी सिस्टम भी तैयार कर रहा है। इसका मकसद यह है कि अगर मुख्य सर्वर में तकनीकी खराबी आती है, तो दूसरा सर्वर तुरंत सेवा संभाल सके। यात्रियों को लंबे समय तक वेबसाइट या एप के ठप होने का सामना न करना पड़े। इसके लिए सिकंदराबाद में बैकअप व्यवस्था विकसित की जा रही है।

37,000 टिकट प्रति मिनट को बढ़ाकर एक लाख करने की योजना

बदलावों के बारे में आईआरसीटीसी ने कहा, बदलाव के तहत सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर में भी सुधार किया जाएगा। अभी सिस्टम करीब 37,000 टिकट प्रति मिनट है जिसे बढ़ाकर एक लाख से अधिक टिकट प्रति मिनट करने की तैयारी है। इस अपग्रेड के लिए करीब 150 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

छत्तीसगढ़ में 31 आईपीएस ऑफिसरों का तबादला

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 31 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस संबंध में गृह (पुलिस) विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। सूची के मुताबिक, महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक और सहायक पुलिस महानिरीक्षक का तबादला किया गया है। जीपी सिंह को राज्य पुलिस अकादमी का डीजी नियुक्त किया गया है। वहीं दीपांशु विजय काबरा को वर्तमान कार्य के अतिरिक्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेल एवं यातायात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पवन देव नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं का डीजी बनाया गया है।

संपादकीय

बीमार हैं स्कूल

राजनीति न करें, सुधार हो मकसद

देश के सरकारी स्कूलों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। जिस देश में एक लाख स्कूल एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हों, मूलभूत शैक्षिक सुविधाओं का अभाव हो, वहां पढ़ाई का स्तर क्या होगा, अंदाज लगाना कठिन नहीं है। कुछ स्कूल जर्जर इमारतों में चल रहे हैं, कुछ पेड़ तले व बरामदों में- तो सवाल स्वाभाविक है कि सुधार क्यों नहीं होता? आखिर इन स्कूलों का सुधार हमारे नीति-नियंताओं की प्राथमिकताओं में क्यों नहीं होता? जिस शिक्षा विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों की पूरी फौज तैनात है, उसकी जवाबदेही तय क्यों नहीं होती? अब भले ही सरकारी स्कूलों को सीजेपी ने अपना मुद्दा बना लिया हो, लेकिन इससे पहले ही देश के कई भागों में छात्र स्कूलों में सुधार की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। विडंबना यह है कि इन स्कूलों पर ग्रामीण, समाज के वंचित वर्गों, श्रमिकों व गरीब बच्चों की निर्भरता अधिक होती है, फलत: उनकी आवाज भी अनसुनी कर दी जाती है। यदि नेताओं और अधिकारियों के बच्चों के लिये सरकारी स्कूलों में भर्ती अनिवार्य कर दी जाती तो शायद इन स्कूलों के दिन फिर जाते। सरकारी स्कूलों का सच किसी से छिपा नहीं है। स्कूलों में छात्रों के दाखिले में कमी का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मुनाफा कमा रहे निजी स्कूलों का कुनबा लगातार बढ़ ही रहा है। उनकी संख्या अब 2.9 लाख से बढ़कर 3.4 लाख के करीब हो गई है। यह एक हकीकत है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर राजनीतिक दलों की जो फिक्र सामने आ रही है, उसके निहितार्थ समझना कठिन नहीं है। इन दलों की सरकारों के दौरान भी इन स्कूलों की दिशा-दशा में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया।

> “ नीति आयोग के हालिया आंकड़े इस सच को अनावृत करते हैं। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दशक में पूरे देश में 94 हजार सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। साथ ही इसी अवधि में सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल भी 83 हजार से घटकर 79 हजार रह गये हैं।

चिंता इस बात को लेकर है कि इस मुद्दे पर जो राजनीति हो रही है, कहीं उसके चलते सुधार के विमर्श पर आंच न आए। सही मायने में सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होना चाहिए। इसमें शासन, प्रशासन, पक्ष-विपक्ष और नागरिकों की भी अहम भूमिका होनी चाहिए। नीति-नियंताओं को सोचना चाहिए कि अभिभावकों से मोटी फीस लेने वाले निजी स्कूल क्यों फल-फूल रहे हैं? सरकारी स्कूलों के पास भवन हैं, पर्याप्त जगह है, सम्मानजनक पगार वाले शिक्षक हैं और सरकारी तंत्र का समर्थन है, तो ये स्कूल पनप क्यों नहीं रहे हैं? क्यों सरकारी स्कूलों में पानी, बिजली, बेंच, टेबल व शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं? बल्कि सुधारों के बजाय शिक्षकों की नियुक्ति में राजनेताओं की धांधली की खबरें अकसर मीडिया में तैरती रहती हैं। विडंबना देखिये कि पढ़ाई-लिखाई के लिये अनुकूल वातावरण की मांग को लेकर राजस्थान व उत्तर प्रदेश के कई शहरों में विद्यार्थी सड़कों पर उतरे हैं। इन बच्चों को अपने भविष्य की फिक्र थी और ये स्कूलों में गुणवत्ता का शैक्षिक वातावरण मांग रहे थे। निश्चित रूप से हमारे नीति-नियंताओं ने सरकारी स्कूलों का उद्धार करने के लिये कभी कोई बड़ा अभियान नहीं चलाया। अब जब मुद्दा तूल पकड़ रहा है तो तमाम घोषणाएं की जा रही हैं। सही मायने में प्राथमिक शिक्षा किसी भी देश के भविष्य की बुनियाद होती है। जब इन स्कूलों में बीमार भविष्य वाले नागरिक तैयार करेंगे तो देश का भला कैसे होगा? दरअसल, सरकारी स्कूल हमारे समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता का पर्याय हैं। जो लोग अपने बच्चों को महंगे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं, वे ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिये मजबूर हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह कि मिड-डे-मील जैसे प्रलोभनों से ये सरकारी स्कूल कब तक अपना अस्तित्व बना पाएंगे? कहीं न कहीं इन स्कूलों की अनदेखी करके हम एक बड़ी आबादी को शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित तो नहीं कर रहे हैं?

स्वास्थ्य अनुसंधान की अनदेखी के चिंताजनक संकेत

दिनेश सी शर्मा

प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति में बायोमेडिकल और स्वास्थ्य अनुसंधान एवं विकास पर खर्च बढ़ाने जैसे लक्ष्य शामिल हैं। लेकिन कुछ पहलू चिंताजनक हैं। मसलन, इसमें हेल्थ रिसर्च के लिए फंड अभी भी नाकाफी रहेगा। वहीं निजी और सीएसआर निवेश को बढ़ावा देने से रिसर्च की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) ने एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति का प्रस्ताव दिया है। यह विभाग करीब दो दशक से मौजूद है, लेकिन अब जाकर इसकी नींद खुली कि भारत में हेल्थ रिसर्च पर कोई खास नीति नहीं है।

जुलाई में जारी अनुसंधान एवं विकास आंकड़ों के अनुसार, देश में स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए मुख्य संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) को राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए रखे फंड का महज 3.3 प्रतिशत हिस्सा मिलता है, जबकि रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों को क्रमश: 32 और 15 फीसदी। भारत का आरएंडडी हेतु रखा गया फंड बहुत कम है -जीडीपी का 0.84 फीसदी, जबकि चीन का 2.58 प्रतिशत है। नई स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के जाहिर लक्ष्यों में से एक बायोमेडिकल और स्वास्थ्य अनुसंधान एवं विकास पर खर्च बढ़ाना है। लक्ष्य है कि स्वास्थ्य अनुसंधान में निवेश को जीडीपी के अंशानुसार वर्तमान में 0.024 फीसदी से बढ़ाकर 2037 तक 0.072 प्रतिशत और 2047 तक 0.15 फीसदी करना है। भले ही यह बढ़ोतरी बड़ी लग सकती है, लेकिन भारत के मौजूदा और अनुमानित बीमारियों के बोझ और उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों की तुलना में यह बहुत कम है। इसके अलावा, प्रस्तावित बढ़ोतरी के लिए समय-सीमा बहुत दूर की है, लक्ष्य प्राप्ति अनिवार्य नहीं व इसके लिए कोई बजटीय मदद भी नहीं है। प्रस्तावित बढ़ोतरी कैसे हासिल की जाएगी, ज़्यादा समस्या वाली बात यह है। नीति में कहा गया है :'सार्वजनिक निवेश धीरे-धीरे बढ़ेगा, और इसके साथ उत्तरदायित्वपूर्ण निजी, परोपकारी और गैर-सरकारी निवेश भी होगा'। यह औपचारिक रूप से स्वास्थ्य अनुसंधान में निजी निवेश के लिए द्वार खोलना है।

सरकार जिस तरह निजी निवेश को बढ़ावा देना चाहती है, वह ज़्यादा चिंता का विषय होना चाहिए। नीति में कहा है कि निजी कंपनियों से मिलने वाले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का इस्तेमाल सार्वजनिक संस्थानों में आरएंडडी प्रोजेक्ट्स के लिए किया जा सकेगा, और सेहत अनुसंधान विभाग ऐसी फंडिंग को आसान बनाने को ज़रूरी नीतियां बनाएगा।

यह तरीका दवा या वैक्सीन विकास के लिए मौजूदा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से अलग है, जिसमें कोविड-19 वैक्सीन के विकास जैसी अहम परियोजना के तहत फार्मा कंपनियां और सार्वजनिक संस्थान शामिल होते थे। अगर किसी कंपनी-चाहे वह फार्मा कंपनी हो या कोई और - अथवा किसी कंपनी द्वारा प्रायोजित परोपकारी संस्था से सीएसआर फंड लेने की इजाज़त दी जाएगी, तो इससे अनुसंधान में पक्षपात हो सकता है या कोई छिपा एजेंडा हो सकता है। जैसे कि पर्यावरण से जुड़े सेहत जोखिम (वायु प्रदूषण, तंबाकू, शराब का प्रभाव), पेशेवराना स्वास्थ्य खतरे, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे विवादित विषयों पर 'वैज्ञानिक संदेह'निर्मित करना।

अजीब बात है कि एक तरफ़ सरकार ने विदेशी योगदान से जुड़े नियमों के नाम पर स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कुछ बड़े स्वास्थ्य एनजीओ और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के जमीनी अनुसंधान अध्ययनों की राह में रोड़े अटका दिए तो दूसरी तरफ़ वह उद्योग जगत और विदेशी संस्थानों द्वारा हेल्थ रिसर्च करने की राह खोल रही है। जबकि स्वदेशी अनुसंधान करने वालों को अभी भी भारतीय व विदेशी अनुसंधानकर्ताओं के बीच वैज्ञानिक सहयोग के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी से मंजूरी लेनी होगी।

ऐसा लगता है कि पूरी सोच स्वास्थ्य अनुसंधान को हर स्तर पर केंद्रीकृत करने और नौकरशाही तंत्र स्थापित करने की है। नीति में एक 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा' बनाने की बात कही गई है जो वृहद स्तर पर प्राथमिकताएं तय करेगा और इस एजेंडा को लागू करने के लिए तीन-स्तरीय प्रशासनिक तंत्र होगा। सबसे ऊपर 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संचालन समिति' होगी जो रणनीतिक दिशा तय करेगी। इसके मुखिया 'प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार' होंगे और इसमें कई नौकरशाह (विज्ञान विभागों के सचिव) सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। दूसरे स्तर पर स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग होगा, जो मुख्य समन्वय एजेंसी के तौर पर काम करेगा, और तीसरे स्तर पर आईसीएमआर होगा, जिसका जिम्मा वैज्ञानिक एवं तकनीक संबंधी कार्य करना होगा। प्रस्तावित प्रशासनिक व्यवस्था राज्यों की भूमिका को कमज़ोर करती है और इस बात को नज़रअंदाज़ करती है कि जनस्वास्थ्य मुख्य रूप से राज्य का विषय है और 'मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान' संविधान की समवर्ती सूची में है। स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा तय करने का अधिकार 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संचालन समिति' को देने से राज्य सिर्फ़ क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी बनकर रह जाएंगे। नीति में कहा गया है, 'राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय स्वास्थ्य ज़रूरतों के हिसाब से काम करने और कार्यक्रम बनाने, बतौर सेवा प्रदाता और जनस्वास्थ्य कार्यक्रम चलाने में मदद करेंगे'।

नीति एक और अहम बदलाव लाती है- 'एकीकृत स्वास्थ्य' को बढ़ावा देने के नाम पर आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक मेडिसिन के लिए रखे अनुसंधान फ़ंड का इस्तेमाल करने की इजाज़त देना। ऐसा तब हो रहा है जब इन पद्धतियों के लिए आयुष मंत्रालय के तहत अलग से रिसर्च फंड और उसके द्वारा चलाए जा रहे तंत्र मौजूद हैं। इससे 'पुष्टिकरण विज्ञान' को बढ़ावा मिलेगा, मसलन, गोमूत्र से इलाज जैसे पारंपरिक ढंग की 'आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए हुई पुष्टि' दिखाना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग जैसी अन्य एजेंसियों से फ़ंडिड प्रोजेक्ट्स के ज़रिए ऐसा पहले ही हो रहा है।

भारत न सिर्फ़ भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से विविधता वाला देश है, बल्कि यहां स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की ज़रूरतों और स्वास्थ्य तंत्र तक पहुंच में असमानताएं भी हैं। मसलन, केरल का स्वास्थ्य सूचकांक और चुनौतियां बिहार या ओडिशा से अलहदा हैं। राज्यों पर केंद्र से थोपा गया एजेंडा लागू करवाने के बजाय, उन्हें अपनी-अपनी प्राथमिकताओं व ज़रूरतों के आधार पर अपना-अपना स्वास्थ्य अनुसंधान ढांचा बनाने और विकसित करने में मदद व मार्गदर्शन दिया जाए। स्वास्थ्य अनुसंधान का मतलब सिर्फ़ नई तकनीक का परीक्षण या नई वैक्सीन और दवाएं बनाना नहीं।

इसके परिणाम स्वास्थ्य नीति और बजट तय करने वाले हों। इसका बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य तंत्र के कामकाज व स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने से जुड़ा है, ताकि बेहतर नतीजे मिल सकें। स्वास्थ्य अनुसंधान एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है, जो सामाजिक-आर्थिक कारकों से गहरी जुड़ी है। मसलन, शहरी गरीब और आदिवासी जैसे हाशिए पर मौजूद समूहों व समुदायों की सेहत समस्याओं पर अक्सर कम रिसर्च होती है। हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज खोले गए। उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर रिसर्च करने को प्रेरित करने की ज़रूरत है।

दीर्घकालीन जरूरतों की खातिर एक समर्पित स्वास्थ्य अनुसंधान नीति बनाने का विचार लंबे समय से महसूस किया जा रहा था। हालांकि, यह नीति जिस दिशा में आगे बढ़ रही है-अनुसंधान एंजेडा विकसित करने को अपनाया केंद्रीकृत तरीका, निजी क्षेत्र को अहम भूमिका देना व आधुनिक मेडिकल स्वास्थ्य अनुसंधान में पारंपरिक चिकित्सा को जोड़ने वाला एजेंडा फिट करना- वह बल्कि ज्यादा हानिकारक है।

लेखक विज्ञान संबंधी विषयों के टिप्पणीकार हैं।

महतारी वंदन योजना: हर बहन के चेहरे पर मुस्कान, विष्णु भैया का यही अरमान

विष्णु प्रसाद वर्मा, सहायक संचालकसंत कच्छप, सहायक संचालक

महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में एक ऐतिहासिक बदलाव लाई है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रूपए सीधे बैंक खाते में मिलती हैं। यह आर्थिक मदद माताओं और बहनों को परिवार की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बना रही है। नारायणपुर जिले के 27 हजार 272 पात्र महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से नियमित आर्थिक सहायता मिल रही है ।

छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो रही है। नारायणपुर जिले के सुदूर और ग्रामीण अंचलों तक इस योजना का सीधा लाभ पहुँच रहा है, जहाँ 27 हजार 272 पात्र महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से नियमित आर्थिक सहायता मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना महिलाओं को न केवल वित्तीय संबल प्रदान कर रही है, बल्कि परिवार और समाज में उनकी निर्णय लेने की क्षमता और सम्मान को भी बढ़ा रही है।

नारायणपुर में योजना का प्रभावी क्रियान्वयन

नारायणपुर जिला अपने भौगोलिक विस्तार और 419 गांवों तथा 2 विकासखंडों के साथ मुख्य रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों से आच्छादित है। ऐसे में प्रतिमाह मिलने वाली एक हजार रुपये की निश्चित राशि इन परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा बनी है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में जिले की 26 हजार 710 पात्र महिलाओं को निरंतर लाभ मिल रहा है। इस तरह द्वितीय चरण में नियद नेल्लानार के तहत सुदूर क्षेत्र के अंतर्गत 562 अतिरिक्त हितग्राहियों को योजना में जोड़ा गया है। जिले की कुल 27 हजार 272 महिलाएं सशक्त हो रही हैं। योजना की शुरुआत से अब तक 30 किस्तों के माध्यम से कुल 74 करोड़ 66 लाख 42 हजार 300 रुपए की राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे जमा की जा चुकी है।

घरेलू जरूरतों से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक सहारा

इस आर्थिक सहायता ने महिलाओं की वित्तीय निर्भरता को खत्म किया है। महिलाएं इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से बेहतर राशन, भोजन और आवश्यक दवाइयों की खरीदारी कर परिवार का पोषण व स्वास्थ्य का देखभाल कर रही है। बच्चों की स्कूल फीस, अध्ययन सामग्री और कपड़ों की व्यवस्था करने में आसानी हो रही है। छोटे-छोटे घरेलू खर्चों को पूरा करने के बाद भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचत की जा रही है। इसके साथ ही रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों और अवसरों पर समय पर मिलने वाली यह राशि महिलाओं के चेहरों पर खुशी और आत्मविश्वास को दोगुना कर देती है।

महतारी वंदन योजना का प्रभाव केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक असर ग्रामीण बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। महिलाओं के पास अतिरिक्त खर्च करने योग्य राशि आने से स्थानीय हाट-बाजारों, छोटी दुकानों और व्यापारियों का कारोबार बढ़ा है। इससे गांव और कस्बों की अर्थव्यवस्था में तरलता बनी हुई है और स्थानीय व्यापार को बल मिल रहा है।

सामाजिक सशक्तिकरण और आत्मसम्मान में वृद्धि

आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद नारायणपुर की महिलाएं अब परिवार के आर्थिक निर्णयों में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। योजना के माध्यम से मिला यह भाई का प्यार और बहनों का सम्मान् राज्य में महिलाओं के सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने का कार्य कर रहा है। महतारी वंदन योजना नारायणपुर जिले की हजारों महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और सामाजिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रही है।

लापरवाही और भ्रष्टाचार पर अंकुश जरूरी

दीपक कुमार शर्मा

सवाल है कि क्या हर बार की बाढ़ व जलभराव समस्या हमारी व्यवस्था की लापरवाही या भ्रष्टाचार है? जहां हर वर्ष नालों की सफाई के नाम पर पैसा खर्च होता है, लेकिन अगली बारिश में वही नाले फिर जाम मिलते हैं। जल निकासी की परियोजनाएं बार-बार बनती हैं, लेकिन जलभराव खत्म नहीं होता, वहां काम की गुणवत्ता और खर्च की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आज सबसे बड़ा सवाल है कि जलभराव के बाद राहत क्यों, संकट आने से पहले तैयारी क्यों नहीं? अधिकांश शहरी जलभराव अचानक पैदा होने वाली समस्या नहीं है। जिन स्थानों पर हर वर्ष पानी भरता है, उनकी पहचान प्रशासन और नगर निकायों को पहले से होती है। यह भी पता होता है कि किस सड़क पर पानी जमा होता है, किस नाले की क्षमता कम है और कहां प्राकृतिक जल निकासी बाधित है। फिर भी हमारा जोर अक्सर पानी भरने के बाद राहत देने पर रहता है, पानी भरने से पहले समस्या रोकने पर नहीं।

इस वर्ष असम में बाढ़ से सैकड़ों लोगों की मौत हुई। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों का दुख है। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के कारण हर वर्ष बाढ़ का खतरा रहता है। केवल भारी बारिश को जिम्मेदार बताकर हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। बाढ़ क्षेत्र पर बढ़ता दबाव, प्राकृतिक जल क्षेत्रों का नुकसान, अनियोजित निर्माण और कमजोर पूर्व चेतावनी व्यवस्था आपदा को अधिक विनाशकारी बना सकती है। हरियाणा की आर्थिक शक्ति गुरुग्राम और देश के प्रमुख कारोबारी केंद्रों में शामिल इस शहर में लाखों लोग काम करते हैं। लेकिन मानसून आते ही कई बार इसकी तस्वीर बदल जाती है। भारी बारिश के बाद सड़कें पानी में डूबती हैं, वाहन घंटों फंसते हैं, सार्वजनिक परिवहन प्रभावित होता है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी रुक जाती है। हर वर्ष नालों की सफाई, पंपों की व्यवस्था और जल निकासी के इंतजाम किए जाते हैं। फिर अगले मानसून में वही स्थान दोबारा पानी में दिखाई देते हैं। पानी भरने के बाद पंप लगाना जरूरी है, लेकिन पंप स्थायी समाधान नहीं है। जलभराव के बाद यातायात नियंत्रित करना जरूरी है, लेकिन उससे बेहतर है कि यातायात प्रभावित ही न हो। पानी निकालना जरूरी है, लेकिन उससे अधिक जरूरी है कि पानी जमा ही न हो।

गुरुग्राम की समस्या को केवल अत्यधिक बारिश कहकर समझना अधूरा होगा। तेजी से बढ़ते निर्माण ने जमीन की पानी सोखने की क्षमता कम कर दी है। जहां कभी खाली जमीन, तालाब, हरित क्षेत्र और प्राकृतिक जल मार्ग थे, वहां सड़कें और इमारतें खड़ी हो गई हैं। बारिश का पानी जमीन में जाने के बजाय तेजी से बहता है और पर्याप्त निकासी न मिलने पर सड़कें जलाशय बन जाती हैं। इस समस्या से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर और देश के अनेक शहर हर वर्ष सामना करते हैं। हमने शहरों का विस्तार तो कर दिया, लेकिन पानी के लिए जगह नहीं छोड़ी। तालाब, झील और प्राकृतिक जल क्षेत्र खाली जमीन नहीं, बल्कि शहरों की प्राकृतिक बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था हैं।

सवाल है कि क्या हर बार की बाढ़ व जलभराव समस्या हमारी व्यवस्था की लापरवाही या भ्रष्टाचार है? जहां हर वर्ष नालों की सफाई के नाम पर पैसा खर्च होता है, लेकिन अगली बारिश में वही नाले फिर जाम मिलते हैं। जल निकासी की परियोजनाएं बार-बार बनती हैं, लेकिन जलभराव खत्म नहीं होता, वहां काम की गुणवत्ता और खर्च की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर किसी अधिकारी, ठेकेदार या एजेंसी की लापरवाही से सार्वजनिक धन खर्च होने के बावजूद समस्या बनी रहती है, तो जवाबदेही किसकी होगी? भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, स्वतंत्र गुणवत्ता जांच और प्राकृतिक जल मार्गों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रत्येक बड़े शहर का वैज्ञानिक बाढ़ जोखिम मानचित्र तैयार होना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट रहे कि अत्यधिक बारिश में पानी किस दिशा में जाएगा। मानसून से पहले नालों की सफाई भी औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। सफाई से पहले और बाद की स्थिति का रिकॉर्ड रखा जाए। हर बड़े जलभराव के बाद केवल पानी निकालने की रिपोर्ट न बने, बल्कि यह भी बताया जाए कि पानी क्यों भरा और अगली बार इसे रोकने के लिए क्या किया जाएगा। शहरों में समय पर बाढ़ चेतावनी की व्यवस्था मजबूत करनी होगी। भारी बारिश की सूचना पहले मिले, यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाए और संवेदनशील इलाकों में प्रशासन पहले से तैनात हो।

गुरुग्राम का जलभराव बताता है कि आधुनिक शहर केवल ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों से नहीं बनता। आधुनिक शहर वह है जो भारी बारिश के दौरान भी अपने नागरिकों को सुरक्षित रख सके। बारिश हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन जल निकासी की योजना, प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, निर्माण पर नियंत्रण, नालों का रखरखाव, पूर्व चेतावनी, विभागों का समन्वय और सार्वजनिक धन में पारदर्शिता हमारे हाथ में है।

अब समय आ गया है कि मानसून के बाद राहत की खबरों के बजाय मानसून से पहले तैयारी की खबरें सुर्खियां बनें। किसी शहर में प्रशासन की असली सफलता यह नहीं कि उसने बाढ़ के बाद कितनी तेजी से पानी निकाला। असली सफलता यह है कि इतनी बारिश के बावजूद शहर डूबा ही नहीं।

संकल्प और कल्याण का महायज्ञ भी

भारतीय धार्मिक परंपरा में रक्षाबंधन केवल एक भाई-बहन का सामान्य पर्व नहीं है, बल्कि यह आपसी स्नेह, सुरक्षा और कर्तव्य का एक गहरा दार्शनिक संकल्प है। श्रावण मास की पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला यह पर्व वैदिक काल के रक्षा-सूत्र की जीवंत परंपरा का आधुनिक रूप है, जो हमें बाहरी संकटों से रक्षा के साथ-साथ एक-दूसरे के कल्याण और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। रक्षाबंधन आते ही आंखों के सामने भाई की कलाई पर बंधी रंग-बिरंगी राखी, बहन की आरती और मिठाई की तस्वीर उभरती है। लेकिन भारतीय धार्मिक परंपरा में 'रक्षा' का विचार केवल भाई-बहन के रिश्ते तक ही सीमित नहीं रहा। राखी के रूप में दिखाई देने वाला यह धागा दरअसल एक बहुत पुराने धार्मिक प्रतीक रक्षा-सूत्र की आधुनिक अभिव्यक्ति है। इसकी मूल भावना किसी प्रिय व्यक्ति के लिए मंगलकामना, उसकी सुरक्षा और धर्म के प्रति उसके संकल्प से जुड़ी रही है। श्रावण मास की शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व रक्षाबंधन इसी व्यापक धार्मिक परंपरा का आधुनिक और लोकप्रिय रूप है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर रक्षा-सूत्र बांधती है और उसके सुख, स्वास्थ्य तथा दीर्घायु की कामना करती है। बदले में भाई उसकी रक्षा का संकल्प लेता है। लेकिन धार्मिक दृष्टि से देखें तो इस छोटे से अनुष्ठान में केवल पारिवारिक स्नेह भर नहीं बल्कि संकल्प, कर्तव्य और कल्याण की भावना भी छिपी है। इसका संबंध श्रावणी या उपाकर्म जैसी वैदिक परंपराओं से भी रहा है। इस दिन अध्ययन, आत्मशुद्धि और जीवनमूल्यों के पुनस्स्मरण से जुड़े अनुष्ठानों की परंपरा रही है। यही कारण है कि रक्षाबंधन का धार्मिक आधार रक्षा की वैदिक अवधारणा से जुड़ा है, जिसमें मनुष्य किसी व्यक्ति, परिवार, समाज और अपने धर्म संकल्प के प्रति जिम्मेदारी स्वीकार करता है। 'रक्षा' का अर्थ सिर्फ सुरक्षा नहीं होता। 'रक्षा' शब्द का सामान्यत: अर्थ खतरे से बचाने का होता है, लेकिन धार्मिक संदर्भ में इसका बहुत व्यापक अर्थ है। धार्मिक परंपरा में रक्षा का मतलब केवल बाहरी संकट से बचाना ही नहीं होता बल्कि उसके कल्याण, दीर्घायु, सद्बुद्धि और धर्मनिष्ठ जीवन की कामना भी रक्षा है। इसलिए संस्कृत के इस प्रसिद्ध मंत्र में महाबली राजा बलि को संबोधित करते हुए कहा गया है—

येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल:।
तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥

जिस रक्षा-सूत्र से महाबली राजा बलि बांधे गए थे, उसी रक्षा से मैं तुम्हें बांधती हूँ; हे रक्षा, तुम अडिग रहो। इस मंत्र का महत्व केवल इतना नहीं है कि इसे राखी बांधते समय बोला जाता है, बल्कि इसमें आया 'मा चल' अर्थात विचलित न होना, का भाव विशेष ध्यान देने योग्य है। इस दृष्टि से राखी किसी कलाई को बांधने से ज्यादा मनुष्य को उसके कर्तव्य से बांधने का प्रतीक बन जाती है।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544
www.onlytds.com

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें...

सामुदायिक सहयोग से कुपोषण के खिलाफ जंग

दुर्ग। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना धमधा के अंतर्गत ग्राम पंचायत करेली में रोटरी क्लब दुर्ग के सहयोग से स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र के कुपोषित बच्चों एवं महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा ग्राम को कुपोषण मुक्त बनाना रहा। शिविर में 71 महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं का शुगर, बीपी एवं हीमोग्लोबिन परीक्षण किया गया। चिकित्सकों ने कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच कर उनके पालकों की काउंसलिंग की। 9 गंभीर कुपोषित बच्चों को दवाइयां वितरित की गईं, जबकि रोटरी क्लब द्वारा 44 कुपोषित बच्चों को सुपोषण किट प्रदान की गई।

राजस्व प्रकरणों में लापरवाही पर तहसीलदार निलंबित

दुर्ग। प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही और जनसमस्याओं के निराकरण में विलंब को गंभीरता से लेते हुए संभागायुक्त दुर्ग सत्य नारायण राठौर ने राजनांदगांव जिले के घुमका तहसील में पदस्थ तहसीलदार मुकेश कुमार ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत की गई है। संभागायुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत निलंबन अवधि में ठाकुर का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, राजनांदगांव निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के लिए 1.050 हेक्टेयर भूमि आबंटित

भिलाई। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देशों तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 4-1 की कंडिका 26 में निहित प्रावधानों के तहत नगर पालिका परिषद अमलेश्वर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण हेतु शासकीय भूमि के आबंटन की स्वीकृति प्रदान की है। जारी आदेश के अनुसार, तहसील पाटन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीन विभिन्न ग्रामों में स्थित कुल 1.050 हेक्टेयर शासकीय भूमि एक रुपए प्रति वर्गफीट की दर से निर्धारित मूल्य राज्य कोष में जमा कराए जाने के उपरांत बिना भू-भाटक के नगर पालिका परिषद अमलेश्वर को हस्तांतरित की गई है।

हर खेत का हो डिजिटल सर्वे, हर किसान का हो पंजीयन

दुर्ग। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण योजना एवं अन्य कृषि सांख्यिकी योजनाओं के संबंध में वार्षिक प्रशिक्षण आज पीडब्ल्यूडी सभागार में सभी अनुविभागीय अधिकारी, उप संचालक कृषि, तहसीलदार एवं पटवारी के लिए आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान अपर कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी भी उपस्थित थे। सहायक अधीक्षक भू- द्वारा अधिकारियों को योजनाओं की प्रक्रिया एवं कार्यों की बारीकियों की विस्तार से जानकारी दी गई।

उत्कृष्ट अपराध विवेचना के लिए दुर्ग पुलिस के 16 अधिकारी व कर्मचारी सम्मानित

■ एसएसपी विजय अग्रवाल ने प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार देकर किया सम्मानित

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। दुर्ग पुलिस द्वारा अपराधों की विवेचना में गुणवत्ता एवं विधिक प्रक्रिया के पालन को प्राथमिकता देते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सोमवार को कंट्रोल रूम भिलाई में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जिले के विभिन्न थानों एवं पुलिस इकाइयों में पदस्थ कुल 16 अधिकारी एवं कर्मचारियों को उत्कृष्ट अपराध विवेचना के लिए चयनित कर सम्मानित किया गया।

सम्मानित अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा विभिन्न प्रकरणों की विवेचना के दौरान तथ्यों का विश्लेषण, साक्ष्यों का संकलन, आवश्यक विधिक कार्यवाही तथा प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी सम्मानित अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र एवं निर्धारित पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया तथा भविष्य में भी गुणवत्तापूर्ण विवेचना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

इन अधिकारियों व कर्मचारियों का हुआ सम्मान

- निरीक्षक बसंत बघेल – थाना प्रभारी, जामगांव (आर)
- उप निरीक्षक पुरुषोत्तम कुर्रे – थाना प्रभारी, कुम्हारी
- उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा – थाना पुलगांव, भिलाई
- उप निरीक्षक चितराम ठाकुर – थाना सुपेला
- उप निरीक्षक सुरेन्द्र नारम – थाना बोरी
- उप निरीक्षक श्रीराम पेण्द्रो – थाना उतई
- उप निरीक्षक दरबारी राम तोरम – थाना यातायात
- उप निरीक्षक मनीष बाजपेई – थाना पद्मनाभपुर
- सहायक उप निरीक्षक सुभाष कोसुर – थाना कुम्हारी
- एएसआई लखन लाल साहू – एसीसीयू दुर्ग
- एएसआई मुरलीधर कश्यप – थाना वैशाली नगर
- एएसआई शशिकला साहू – थाना वैशाली नगर
- एएसआई इतवारी राम डहरे – थाना छावनी
- एएसआई रामकृष्ण तिवारी – थाना दुर्ग
- एएसआई जितेन्द्र चंद्राकर – खंड दुर्ग
- एएसआई मीरा वर्मा – प्रभारी रक्षा टीम

स्कूली छात्र-छात्राओं ने पड़ा साइबर जागरूकता का पाठ, एक्सपर्टस् ने दिए बचाव के टिप्स

■ एसएसएस सेक्टर-10 में साइबर सुरक्षा जागरूकता पर कार्यशाला का आयोजन

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर-10, भिलाई में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को बढ़ते साइबर अपराधों तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं के लगभग 400 विद्यार्थियों तथा विद्यालय के लगभग 40 शिक्षक-शिक्षिकाओं ने सहभागिता की।

कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में सीएसपी, भिलाई निशांत पाठक उपस्थित रहे। इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित इंस्पेक्टर डॉ. संकल्प राय ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को साइबर सुरक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराधों के स्वरूप और ऑनलाइन ठगी के विभिन्न तरीकों से अवगत कराते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय सतर्कता बरतने पर जोर दिया।

संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, रहें सावधान

वक्ताओं ने विद्यार्थियों को विशेष रूप से संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने, अनजान कॉल एवं संदेशों से सावधान रहने तथा ओटीपी, पासवर्ड, बैंक खाते और अन्य संवेदनशील जानकारी किसी के साथ साझा न करने की सलाह दी। साथ ही सोशल मीडिया का सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग, मजबूत पासवर्ड रखने, अनजान व्यक्तियों से ऑनलाइन संपर्क में सावधानी बरतने तथा किसी भी संदिग्ध डिजिटल गतिविधि की स्थिति में तत्काल अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को जानकारी देने के महत्व को रेखांकित किया।

जागरूकता के साथ विद्यार्थियों को यह समझाने पर जोर

कार्यशाला में साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूकता के साथ-साथ विद्यार्थियों को यह समझाने पर भी जोर दिया गया कि साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि प्रत्येक डिजिटल उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। वक्ताओं ने विद्यार्थियों से सुरक्षित डिजिटल आदतों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने तथा साइबर सुरक्षा से संबंधित जानकारी अपने परिवार एवं आसपास के लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस प्रकार विद्यार्थी अपने परिवार और समाज में साइबर जागरूकता के प्रभावी वाहक की भूमिका निभा सकते हैं।

साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता समय की जरूरत

विद्यालय की प्राचार्या सुमिता सरकार ने भी साइबर सुरक्षा के महत्व पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ विद्यार्थियों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से सतर्क और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार अपनाने का आग्रह किया। कार्यशाला के दौरान विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने साइबर सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझा। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल साइबर अपराधों के प्रति चेतावनी देना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में सुरक्षित, सजग और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार की आदत विकसित करना भी रहा। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ व्याख्याता तरुण कुमार साहू ने किया। अंत में उप-प्राचार्या सविता तिवारी ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, वक्ताओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सभी के योगदान की सराहना की।

ईद मिलाद के जुलूस को लेकर दुर्ग पुलिस ने दिए निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। ईद मिलाद-उन-नबी पर्व के अवसर पर प्रस्तावित जुलूसों को दृष्टिगत रखते हुए शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात व्यवस्था सुचारू रखने पुलिस कंट्रोल रूम, सेक्टर-06, भिलाई में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दुर्ग वीरेन्द्र सिंह, एएसपी शहर दुर्ग शोभराज अग्रवाल, एएसपी यातायात कौशलेन्द्र देव पटेल, सीएसपी दुर्ग हर्षित मेहर, डिप्टी कलेक्टर प्रेमलाल साव, सीएसपी भिलाई नगर श्री निशांत पाठक एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात विशाल सोन उपस्थित रहे।

बैठक में भिलाई एवं दुर्ग के मुस्लिम कमेटी के प्रमुखों एवं सदस्यों से चर्चा कर जुलूस को निर्धारित मार्ग एवं समय के अनुसार संचालित करने तथा समय पर समाप्त करने के संबंध में आवश्यक समझाईश दी गई।

जुलूस के दौरान पर्याप्त संख्या में वालेंटियर रखने एवं उनकी सूची संबंधित थाना में पर्व से पूर्व उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देशित किया गया। साथ ही जुलूस के दौरान विशेष रूप से छोटे बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान रखने तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न होने देने के संबंध में समझाईश दी गई। मुस्लिम कमेटी के प्रमुखों एवं सदस्यों द्वारा निर्धारित मार्ग एवं समय का पालन करते हुए जुलूस को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से आयोजित करने तथा पुलिस एवं प्रशासन को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया गया।

विधायक ने किया भूमिपूजन, शिवपारा मरोदा में एक करोड़ की लागत से होंगे विकास कार्य

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। रिसाली निगम क्षेत्र के श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र शिवपारा, बीआरपी कॉलोनी, एचएससीएल कॉलोनी मरोदा क्षेत्र में एक करोड़ बहत्तर लाख छियानबे हजार से विकास कार्य होगा। रविवार को दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने नारियल तोड़कर कार्य को आरंभ कराया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि विकास के लिए सरकार के पास पर्याप्त राशि है। सुविधाओं के लिए खर्च करना सरकार की पहली प्राथमिकता है।

दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर भूमिपूजन करने सबसे पहले वार्ड 17 शिवपारा स्टेशन मरोदा पहुंचे। इसके बाद क्रमश वार्ड 18 एचएससीएल स्टेशन मरोदा व बीआरपी कॉलोनी पहुंचे। विधायक ने नागरिकों से कहा कि निगम क्षेत्र के अंतिम छोर पुरैना से भूमिपूजन करते आ रहे है। क्षेत्रीय पार्षद के

प्रयास और नागरिकों के प्राथमिकता को देखते हुए विभिन्न विकास कार्य को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से कहा कि बहुत सारे विकास कार्यों की मंजूरी प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति पश्चात वें पुन: वार्डो में दौरा करेंगे। भूमिपूजन कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष शैलेन्द्र साहू, पार्षद गजेन्द्री कोठारी, रेखा देवी, ममता सिन्हा, धर्मेन्द्र भगत, सारिका साहू, मंडल अध्यक्ष राजू जंघेल, अनुपम साहू समेत बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

थाने में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के संयुक्त तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण, हरियाली को बढ़ावा देने और शहर को स्वच्छ एवं हरा-भरा बनाने के उद्देश्य से लगातार विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं पौधरोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में नगर निगम के जोन-2 वैशाली नगर अंतर्गत जामुल थाना परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान थाना परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए।

वृक्षारोपण कार्यक्रम का उद्देश्य परिसर को हराभरा बनाने के साथ-

साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना रहा। पौधों के बढ़ने के साथ परिसर में हरियाली बढ़ेगी, जिससे वातावरण भी स्वच्छ एवं अनुकूल रहेगा। इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने पौधों के संरक्षण और उनकी नियमित देखभाल की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण एवं पर्यावरणीय असंतुलन को देखते हुए अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाना आवश्यक है। केवल पौधरोपण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और सुरक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से रोपे गए पौधों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। कार्यक्रम के दौरान सभी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक रूप से अपनी सहभागिता निभाई तथा अधिक से अधिक लोगों को पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया।

निगम की ओर से नागरिकों से अपील की गई कि वे अपने घरों, संस्थानों एवं आसपास उपलब्ध स्थानों पर पौधे लगाएं तथा लगाए गए पौधों को नियमित रूप से पानी देने और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभाएं। सामूहिक प्रयासों से ही भिलाई शहर को अधिक हरा-भरा, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकता है।

उद्यमिता दिवस पर भिलाई चेम्बर पहुंचा आई-हब अहमदाबाद

■ अहमदाबाद स्थित आईहब में उद्यमिता दिवस सेलिब्रेशन

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। उद्यमिता दिवस के अवसर पर Vision Gen Z की टीम ने चेम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री अजय भसीन के नेतृत्व में अहमदाबाद स्थित i-Hub में उद्यमिता दिवस सेलिब्रेशन में भाग लिया। कार्यक्रम में युवाओं ने उद्यमिता, स्टार्टअप, नवाचार एवं भविष्य के व्यवसायिक अवसरों को समझने का अवसर प्राप्त किया।

कार्यक्रम में i-Hub के CEO डॉ. हिरणमय महंता जी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि विचार की ताकत इंटरप्रेन्योर की पहली ताकत है। उन्होंने कहा कि किसी भी उद्यम की शुरुआत एक विचार से

होती है और उस विचार को सही दिशा, मेहनत, नवाचार तथा दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाकर सफल उद्यम में परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं को नए विचारों के साथ आगे आने और उद्यमिता को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित चेम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री अजय भसीन ने भी युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उद्यमिता अपने करियर और लक्ष्यों को संचालित करने का कार्य है। उन्होंने कहा कि आज का युवा नौकरी तलाशने वाला ही नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला भी बन सकता है। इसके लिए सही सोच, कौशल, तकनीक, वित्तीय समझ और मार्गदर्शन आवश्यक है। कार्यक्रम में डॉ जय ध्रुव (प्रान्त संपर्क गुजरात) भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए।

Vision Gen Z के युवाओं ने i-Hub की विभिन्न गतिविधियों एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम की जानकारी प्राप्त की तथा उद्यमिता के क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं को करीब से समझा। कार्यक्रम ने युवाओं में सोचो, सीखो और अपना उद्यम खड़ा करो की भावना को मजबूत किया। उद्यमिता दिवस का यह आयोजन युवाओं के लिए प्रेरणादायी रहा और उन्हें भविष्य में नए विचारों के साथ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान सभी युवाओं ने अपनी समस्याओ को महंता जी के समक्ष रखा समाधन पाकर सभी युवा हर्षित थे। यह जानकारी शंकर सचदेव ने दी।

प्लेट मिल ने फिनिश्ड प्लेट्स के रोड डिस्पैच का नया दैनिक रिकॉर्ड बनाया

भिलाई। इस्पात संयंत्र के प्लेट मिल के डिस्पैच सेक्शन ने फिनिश्ड प्लेट्स के रोड डिस्पैच का नया दैनिक रिकॉर्ड स्थापित किया है। टीम ने एक दिन में 49 ट्रॉलियों के माध्यम से 1,526 टन फिनिश्ड प्लेट्स का रोड डिस्पैच कर यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। इससे पूर्व 16 अगस्त 2026 को 40 ट्रॉलियों के माध्यम से 1,246 टन फिनिश्ड प्लेट्स डिस्पैच रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। इस प्रकार पिछले रिकॉर्ड की तुलना में एक दिन में 9 अधिक ट्रॉलियों के माध्यम से 280 टन अधिक फिनिश्ड प्लेट्स का डिस्पैच किया गया।

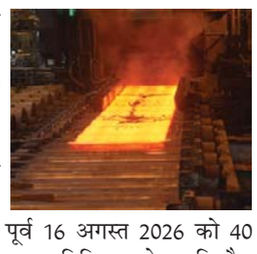

यह उपलब्धि प्लेट मिल के डिस्पैच सेक्शन, ऑपरेशन एवं लॉजिस्टिक्स टीम, ट्रांसपोर्टर, क्रेन एवं हैंडलिंग टीम सहित सुचारू और तेज प्रेषण प्रक्रिया में योगदान देने वाले सभी संबंधित विभागों एवं हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय, बेहतर योजना और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। सड़क मार्ग से प्रेषण में स्थापित यह नया दैनिक रिकॉर्ड प्लेट मिल, सेलङ्कबीएसपी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और प्रेषण दक्षता के क्षेत्र में एक नया मानदंड प्रस्तुत करता है। यह सामूहिक टीमवर्क, कार्यकुशलता और निरंतर बेहतर प्रदर्शन की दिशा में टीम की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।

Since 1972
CROWN-TV
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size
CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास-खबर

सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान अंतर्गत ग्राम पैजनी शिविर का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

बलौदाबाजार। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने 'सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान' के तहत तहसील लवन के ग्राम पैजनी में आयोजित शिविर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाने और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीयन में प्रगति लाने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिये। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना से छूटे हुए सभी पात्र हितग्राहियों को शतप्रतिश लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी जरूरतमंद वंचित न रहे। इस शिविर क उद्देश्य है कि सभी 31 योजनाओं का संतृप्तिकरण हो। उन्होंने कहा कि शिविर के एक दिन पूर्व छूटे हुए हितग्राहियों से संपर्क कर शिविर की जानकारी दें और योजना क लाभ दिलाएं। इस दौरान उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से पटवारी,सचिव द्व2 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की नियमित उपस्थिति, पीडीएस दुकान, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं स्कूलों की जानकारी ली। उन्होंने प्राथमिक स्कूल पहुंच मार्ग मरम्मत एवं शौचालय की साफ-सफाई दुरस्त करने के निर्देश दिये।

रावघाट माइन्स प्रभावित ग्रामों के ग्रामीणों ने कलेक्टर से भेंट कर रखीं समस्याएं

कांकेर। कलेक्टर कुंदन कुमार से रावघाट माइन्स श्रमिक विकास समिति के सदस्यों ने आज सौजन्य भेंट की तथा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं व बहुप्रतीक्षित मांगों को लेकर आवेदन सौंपा। इस पर कलेक्टर ने कहा कि वे जल्द ही माइन्स प्रभावित ग्रामों का दौरा कर वहां के ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनेंगे व जिला प्रशासन द्वारा हरसंभव सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुदूर अंचल में निवासरत ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण उनकी पहली प्राथमिकता है। अंतागढ़ विकासखण्ड के रावघाट परियोजना क्षेत्र की 08 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने को कलेक्टर कुमार से सौजन्य भेंट की। माइन्स श्रमिक विकास समिति के बंशीलाल दुग्गा, प्यारेलाल उसेण्डी, बीरसिंह गावड़े, हेमराज देहारी तथा संतोष सुखदेवे ने बताया कि अंतागढ़ से नारायणपुर मार्ग अत्यंत जर्जर हो गया है।

महतारी वंदन से बदली सोचः बेटी के भविष्य के लिए हर महीने कर रहीं निवेश

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ उनके परिवार के भविष्य को भी नई दिशा दे रही है। मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के सुदूर वनांचल ग्राम चकदा की रहने वाली केशमती बैगा इसकी प्रेरक मिसाल बनकर उभरी हैं। मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करने वाली केशमती महतारी वंदन योजना से प्रतिमाह मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता राशि को खर्च करने के बजाय अपनी बेटी के उज्वल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में नियमित रूप से जमा कर रही हैं। आर्थिक रूप से सीमित संसाधनों के बावजूद केशमती ने यह साबित किया है कि छोटी-छोटी बचत भी भविष्य की बड़ी सुरक्षा बन सकती है। उनका मानना है कि आज की यह नियमित बचत आगे चलकर बेटी की शिक्षा, उच्च अध्ययन और अन्य आवश्यकताओं में मजबूत सहारा बनेगी।

सेना के सम्मान में राखी का धागा, नवा रायपुर के पोस्टकार्ड पर विद्यार्थियों ने लिखे भावपूर्ण संदेश...

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राखी में भारतीय सेना के जवानों के सम्मान और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भावनात्मक एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के अधिकारियों, जूनियर कमीशंड अधिकारियों एवं अन्य रैंक सहित कुल 72 सैन्यकर्मियों ने सहभागिता की।

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की छात्राओं ने सैन्यकर्मियों की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। छात्राओं ने देश की सीमाओं की रक्षा में दिन-रात समर्पित जवानों के प्रति सम्मान, स्नेह और आभार व्यक्त किया। राखी के इस पवित्र धागे ने सैनिकों और विद्यार्थियों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत किया। नवा रायपुर के पोस्टकार्ड पर देश के रक्षकों के नाम लिखी भावनाएं

कार्यक्रम की विशेष पहल के रूप में विद्यार्थियों ने नवा रायपुर के पोस्टकार्ड पर भारतीय सेना के जवानों के लिए अपने हाथों से व्यक्तिगत पत्र एवं संदेश लिखे। इन संदेशों में विद्यार्थियों ने सैनिकों के साहस, त्याग और देशसेवा के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए उनके सुरक्षित रहने और देश की रक्षा में सदैव सफल होने की कामना की। बच्चों के इन भावपूर्ण संदेशों ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया।

इस अवसर पर सैन्यकर्मियों ने विद्यार्थियों से संवाद किया और भारतीय सेना के जीवन, अनुशासन एवं कार्यप्रणाली से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाने, जिम्मेदार नागरिक बनने और राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। संवाद के माध्यम से विद्यार्थियों को सेना के जीवन को करीब से समझने और सैनिकों के समर्पण एवं चुनौतियों को जानने का अवसर मिला। कार्यक्रम के सफल आयोजन में स्टेशन मुख्यालय, रायपुर के प्रशासनिक कमांडेंट कर्नल अभिषेक उनियाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम के समन्वय एवं संचालन में सूबेदार राज किशोर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इस अवसर पर कर्नल अरिंदम मजूमदार, विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम केवल राखी बांधने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विद्यार्थियों ने अपने संदेशों और भावनाओं के माध्यम से देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और राष्ट्रभक्ति का भाव प्रकट किया।

नवा रायपुर के पोस्टकार्ड पर लिखे बच्चों के संदेशों में देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों के प्रति पूरे समाज की श्रद्धा और विश्वास की झलक दिखाई दी।

घुमड़ते बादलों के बीच मुक्ताकाशी मंच पर साकार हुआ 'पावस प्रसंग'

सावन की फुहारों के बीच कथक और शास्त्रीय संगीत ने बांधा समा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राजधानी रायपुर के मुक्ताकाशी मंच पर घुमड़ते बादलों, सावन की फुहारों और सुर-ताल की मनोहारी संगति के बीच 'पावस प्रसंग' का भव्य सांस्कृतिक आयोजन हुआ। प्रकृति के मनोहारी परिवेश में शास्त्रीय नृत्य और संगीत की भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने वर्षा ऋतु की अनुभूतियों को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम के दौरान वातावरण कभी बादलों की गरज से गूंजा तो कभी शास्त्रीय सुरों और घुंघरुओं की झंकार से संगीतमय हो उठा।

'पावस प्रसंग' में वर्षा ऋतु के विविध भावों को कथक नृत्य और शास्त्रीय गायन के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में सुश्री शाश्वती बैनर्जी ने कथक नृत्य की भावपूर्ण प्रस्तुति से सावन की उमंग, बादलों की गरज और वर्षा की रिमझिम को नृत्य मुद्राओं के माध्यम से साकार किया। उनकी प्रस्तुति में भाव, लय और ताल का सुंदर समन्वय देखने को मिला।

इसके साथ ही मेघा बोस ने शास्त्रीय गायन की मनोहारी प्रस्तुति दी। उनके सुमधुर स्वरों ने पावस ऋतु की कोमल अनुभूतियों को स्वर प्रदान किया और उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुक्ताकाशी मंच पर शास्त्रीय संगीत की यह प्रस्तुति विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रही।

सुश्री इशिका गिरी ने भी कथक नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति देकर दर्शकों की खूब सराहना बटोरी। उनकी नृत्य प्रस्तुति में शास्त्रीय नृत्य की बारीकियों के साथ वर्षा ऋतु के उल्लास और सौंदर्य का प्रभावी चित्रण दिखाई दिया। वहीं मेवाती घराने के शास्त्रीय गायक श्री प्रदीप कुमार चौबे ने अपनी सुमधुर गायकी से पावस ऋतु की अनुभूतियों को सुरों में पिरोया। उनकी प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को सुरमयी बना दिया।

कार्यक्रम के दौरान साहित्य परिषद के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा ने मंच पर प्रतिभागी कलाकारों को सम्मानित किया। उन्होंने कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय शास्त्रीय कला परंपरा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है और कला के प्रति नई पीढ़ी की रुचि भी बढ़ती है।

कार्यक्रम के संचालक डॉ. संजय कनौजे ने भी कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने प्रस्तुतियों की प्रशंसा करते हुए कलाकारों को विभिन्न मंचों पर सम्मान और प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कला और संस्कृति समाज को संवेदनशील बनाने के साथ हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। कार्यक्रम में उप संचालक उमेश मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार एवं फोटोग्राफर दीपेंद्र दीवान तथा उदयभान सिंह सहित बड़ी संख्या में कला प्रेमी, श्रोता और दर्शक उपस्थित रहे। खुले आकाश के नीचे बादलों से घिरे मनोहारी वातावरण में शास्त्रीय संगीत और कथक की प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों को पावस ऋतु के सौंदर्य का अनूठा अनुभव कराया। 'पावस प्रसंग' की शाम प्रकृति और कला के अद्भुत संगम की साक्षी बनी। एक ओर आसमान में घुमड़ते बादल और सावन की फुहारें थीं, तो दूसरी ओर मंच पर कथक की लय, घुंघरुओं की झंकार और शास्त्रीय गायन के मधुर सुर। कलाकारों की भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने सावन के रंग, उमंग और संवेदनाओं को इस तरह साकार किया कि मुक्ताकाशी मंच पर पावस केवल मौसम नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक अनुभूति बन गया।

चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से बच्चों को अधिकार और सुरक्षा की जानकारी, विद्यालयों में निरंतर जागरूकता अभियान

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। जांजगीर -चाम्पा जिले में बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से विद्यालयों में निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आयोजित इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण, बाल अधिकारों और संकट की स्थिति में सहायता प्राप्त करने के उपायों की जानकारी दी जा रही है।

इसी क्रम में शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीबाई, चांपा तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोखरा में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने विद्यार्थियों को बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा, बाल श्रम निषेध, बाल विवाह रोकथाम, बाल तस्करी तथा बच्चों से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।

विद्यार्थियों को बताया गया कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 बच्चों के लिए 24 घंटे एवं सप्ताह के सातों दिन संचालित निःशुल्क आपातकालीन सेवा है। अनाथ, बेसहारा, बाल श्रम में संलिप्त, बाल विवाह की आशंका वाले, शोषण अथवा दुर्व्यवहार से प्रभावित या किसी अन्य संकटपूर्ण परिस्थिति में रहने वाले बच्चों की सूचना 1098 पर दी जा सकती है। सूचना मिलने पर संबंधित टीम द्वारा त्वरित हस्तक्षेप करते हुए बच्चे को आवश्यक संरक्षण एवं पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाती है।

जागरूकता कार्यक्रम में बच्चों को बहला-फुसलाकर ले जाने, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग, बाल तस्करी तथा किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से बचाव के उपाय बताए गए। विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

उन्हें समझाया गया कि किसी विपरीत परिस्थिति में भयभीत होने के बजाय तत्काल माता-पिता, शिक्षक या किसी विश्वसनीय वयस्क को इसकी जानकारी दें और आवश्यकता पड़ने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 से संपर्क करें। वीडियो प्रस्तुति एवं संवादात्मक सत्र के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों की जानकारी दी गई।

राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा आज से 08 सितम्बर तक

नेत्रदान-महादान, जीवन का सबसे बड़ा वरदान

श्रीकंचनपथ समाचार

कवर्धा। राष्ट्रीय अंधत्व एवं अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कबीरधाम जिले में 25 अगस्त से 08 सितम्बर 2026 तक 41वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान आमजन को नेत्रदान के महत्व के प्रति जागरूक करने, अधिक से अधिक लोगों को मरणोपरांत नेत्रदान का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करने तथा नेत्रदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। यह कार्यक्रम कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डी.के. तुरे एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्रीमती अनुपमा तिवारी के नेतृत्व तथा जिला नोडल अधिकारी डॉ. क्षमा चोपड़ा के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है।

जिला नोडल अधिकारी डॉ. क्षमा चोपड़ा ने बताया कि भारत में बड़ी संख्या में लोग कॉर्नियल अंधत्व से पीड़ित हैं और दृष्टि की रोशनी पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आंखों से प्राप्त कॉर्निया दो जरूरतमंद लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है। इसलिए नेत्रदान मानवता की सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। नेत्रदान के माध्यम से मृत्यु के बाद भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में रोशनी लाई जा सकती है। आपकी आंखें दो लोगों को नई दृष्टि प्रदान कर उन्हें रंगीन दुनिया देखने का अवसर दे सकती हैं। इसी उद्देश्य से इस वर्ष राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े के दौरान आमजन से नेत्रदान का संकल्प लेने की अपील की जा रही है।

जिला नोडल अधिकारी डॉ. क्षमा चोपड़ा ने बताया कि चश्मा लगाने वाले व्यक्ति, मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति तथा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं। मृत्यु के बाद आंखों से कॉर्निया निकालने की प्रक्रिया में सामान्यतः 10 से 15 मिनट का समय लगता है। इससे चेहरे पर किसी प्रकार की विरूपता नहीं आती। मृत्यु के 6 घंटे के भीतर कॉर्निया निकालना आवश्यक होता है। इसलिए मृत्यु की सूचना मिलते ही संबंधित नेत्र बैंक अथवा स्वास्थ्य विभाग को तत्काल सूचित करना चाहिए। नेत्रदान की प्रक्रिया के कारण अंतिम संस्कार में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होती है। अपने नजदीकी नेत्र बैंक अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल के नेत्र विभाग से संपर्क कर नेत्रदान का संकल्प पत्र भर सकते हैं।

श्रावण के अंतिम सोमवार को अमरकंटक पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

मां नर्मदा के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की

एसआर पाराशर

रायपुर। श्रावण मास के अंतिम सोमवार के पावन अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने मध्यप्रदेश के पवित्र तीर्थस्थल अमरकंटक पहुंचकर मां नर्मदा के दर्शन किए। उन्होंने नर्मदा उद्गम स्थल स्थित नर्मदा कुंड में विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। इसके पश्चात उन्होंने जलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का पूजन किया और प्रदेश एवं प्रदेशवासियों के कल्याण की प्रार्थना की।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने नर्मदा कुंड एवं नर्मदा उद्गम स्थल के पवित्र परिसर में पूजा-अर्चना कर मां नर्मदा का आशीर्वाद लिया। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को अमरकंटक में श्रद्धा और आस्था का विशेष वातावरण रहा। इस दौरान श्री शर्मा ने धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जनकल्याण की भावना को सर्वोपरि रखते हुए प्रदेश की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की।

अमरकंटक प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कांवड़ियों के बीच भी पहुंचे। उन्होंने मृत्युंजय आश्रम में कांवड़ियों को भोजन प्रसादी वितरित की और उनके साथ बैठकर प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से आत्मीय बातचीत कर उनकी कांवड़ यात्रा, यात्रा मार्ग और उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। कांवड़ियों के साथ सहजता से संवाद करते हुए उन्होंने उनकी यात्रा के अनुभव भी सुने।

उल्लेखनीय है कि अमरकंटक से भोरमदेव मंदिर तक लगभग 150 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।

यात्रा मार्ग पर कांवड़ियों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, भोजन और रात्रि विश्राम सहित आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्ग में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस पेट्रोलिंग दल भी तैनात किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

अमरकंटक स्थित मृत्युंजय आश्रम में कांवड़ियों के लिए निःशुल्क भोजन एवं रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। यहां श्रद्धालुओं को दाल-भात, सब्जी के साथ खीर, पूरी और हलवा सहित भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे लंबी कांवड़ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को विश्राम के साथ पौष्टिक भोजन की सुविधा मिल रही है।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सावन माह के इस पवित्र अवसर पर भोरमदेव से अमरकंटक तक श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी कांवड़ यात्रा को सुगम बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि सभी भक्तजन श्रद्धा, उत्साह और सुरक्षित वातावरण में अपनी कांवड़ यात्रा पूरी कर सकें।

कलेक्टर ने परखी डिजिटल गिरदावरी और आयुष्मान शिविरों की जमीनी हकीकत

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की मंशा के अनुरूप सुकमा जिला प्रशासन द्वारा गांव-गांव में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। वन एवं सुकमा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में प्रशासन द्वारा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इसी क्रम में कलेक्टर अमित कुमार ने सोमवार को छिंदगढ़ विकासखंड के सुदूर वनांचल क्षेत्रों का दौरा कर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पालेम, कावराकोपा, पेरमारास और टाहकवाड़ा पहुंचकर शिविरों की व्यवस्थाएं देखीं और ग्रामीणों से सीधे संवाद किया।

पालेम पंचायत में आयोजित आयुष्मान कार्ड शिविर में कलेक्टर श्री अमित कुमार ने हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया को नजदीक से देखा। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से आवश्यक दस्तावेज और पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी लेने के बाद उन्होंने स्वयं कंप्यूटर पर बैठकर हितग्राही देवे वेट्टी का आयुष्मान कार्ड के लिए पंजीयन किया।

कलेक्टर ने पोर्टल पर आवश्यक जानकारी दर्ज करने के साथ हितग्राही का फोटो भी स्वयं लिया। कलेक्टर की इस पहल से ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला। उन्होंने ग्रामीणों से अधिक से अधिक संख्या में आयुष्मान योजना से जुड़कर निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लेने की अपील की।

कलेक्टर ने कावराकोपा में संचालित डिजिटल क्रॉप सर्वे (डिजिटल गिरदावरी) का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से सर्वे की प्रक्रिया और प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि खेत में जाकर फसल की स्थिति का जियो-टैग्ड फोटो लेकर ऑनलाइन अपलोड करने की व्यवस्था से गिरदावरी कार्य में पारदर्शिता बढ़ी है। इससे वास्तविक फसल की जानकारी दर्ज करने में मदद मिलती है और गलत प्रविष्टियों की संभावना कम होती है। कलेक्टर ने एसडीएम छिंदगढ़ श्री पी.वी. खेस की उपस्थिति में पेरमारास और टाहकवाड़ा में आयोजित आयुष्मान शिविरों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों को पंजीयन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो और पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए।

गांव-गांव पहुंच रही स्वास्थ्य सुरक्षा: सुकमा जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रशासन द्वारा मेगा आयुष्मान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। छिंदगढ़ विकासखंड के गांवों में शिविर लगाकर पात्र ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। कलेक्टर की सक्रिय फील्ड मौजूदगी से प्रशासनिक अमले में भी उत्साह बढ़ा है। वहीं ग्रामीणों में शासन की योजनाओं के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप शासन की प्राथमिकता है कि दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक स्वास्थ्य, कृषि और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे।

प्रभारी मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में सुकमा जिला प्रशासन इसी दिशा में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार मैदानी स्तर पर कार्य कर रहा है।

'जन गण मन' सुनते ही भूमि पेडनेकर ने छोड़ा रेड कार्पेट

अटेंशन में खड़ी हुईं तो फैंस बोले- 'वेल डन'

बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। मुंबई के एक इवेंट में भूमि रेड कार्पेट पर पैपराजी के लिए पोज दे रही थीं, तभी नेशनल एंथम 'जन गण मन' बजने लगा। राष्ट्रगान की आवाज सुनते ही एक्ट्रेस ने तुरंत फोटो के लिए पोज देना बंद कर दिया और रेड कार्पेट से हट गईं। उनका ये अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को काफी पसंद आया है।

'एक सेकंड, नेशनल एंथम'

भूमि पेडनेकर रविवार, 23 अगस्त को मुंबई में एक इवेंट में पहुंची थीं। इस दौरान वो रेड कार्पेट पर फोटोग्राफर्स के लिए पोज दे रही थीं। तभी वहां नेशनल एंथम बजना शुरू हुआ।

भूमि ने तुरंत पैपराजी से कहा, 'एक सेकंड, नेशनल एंथम' इसके बाद वह रेड कार्पेट से एक तरफ हट गईं और सम्मान में अटेंशन की मुद्रा में खड़ी हो गईं। राष्ट्रगान खत्म होने के बाद वह दोबारा रेड कार्पेट पर लौटीं और पैपराजी के लिए पोज देने लगीं।

सोशल मीडिया पर छा गया वीडियो

भूमि का ये पल कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स ने राष्ट्रगान के दौरान सम्मान दिखाने के लिए एक्ट्रेस की तारीफ की।

एक यूजर ने भूमि के इस जेस्चर की तारीफ करते हुए लिखा कि बहुत कम लोग इस बात को समझ सकते हैं। वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, 'उनका सम्मान।' कई अन्य यूजर्स ने भी भूमि के इस अंदाज को 'रिस्पेक्ट' और 'वेल डन' बताया। भूमि ने फिलहाल इस वायरल वीडियो को लेकर अलग से कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि, वीडियो में नजर आए उनके इस जेस्चर की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है।

'दलदल' में नजर आई थीं भूमि

वर्कफ्रंट की बात करें तो भूमि पेडनेकर को आखिरी बार साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज 'दलदल' में देखा गया था। यह सीरीज विष धमीजा के बेस्टसेलिंग नॉवेल 'भिंडी बाजार' पर आधारित है। प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई इस सीरीज में भूमि ने डीसीपी रीता फरेरा का किरदार निभाया था।

इससे पहले वह साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'मेरे हस्बैंड की बीवी' में अर्जुन कपूर और रकुल प्रीत सिंह के साथ नजर आई थीं। हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास असर नहीं छोड़ पाई थी।

'मैं मर्दों से नफरत नहीं करती'

क्लाइमेट चेंज और पेट्रियार्की वाले बयान पर दीया मिर्जा ने दी सफाई

एक्ट्रेस और पर्यावरण कार्यकर्ता दीया मिर्जा ने क्लाइमेट चेंज और पेट्रियार्की को लेकर अपने पुराने बयान पर सफाई दी है। जूम को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब वह क्लाइमेट चेंज के लिए पेट्रियार्की को जिम्मेदार बताती हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो पुरुषों से नफरत करती हैं। दीया ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और उनके खिलाफ एक ऐसी कहानी बनाई गई, जिसमें उन्हें 'मर्दों से नफरत करने वाली' बताया गया।

'पेट्रियार्की को समझना होगा'

दीया ने कहा कि पेट्रियार्की का मुद्दा पुरुषों को दोषी ठहराने का नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच को समझने का है जो बराबरी, संसाधनों की कद्र और उनकी सुरक्षा को पर्याप्त महत्व नहीं देती।

उनके मुताबिक, पेट्रियार्कल सोच संसाधनों के इस्तेमाल और शोषण को बढ़ावा देती है, जबकि बराबरी, परवरिश, हमदर्दी और प्यार पर आधारित सोच दुनिया को अलग नजरिए से देखती है। दीया ने सवाल उठाया कि आखिर दुनिया में ऐसी चीजें सामान्य क्यों हो गई हैं, जिनसे बड़े स्तर पर नुकसान और तबाही हो रही

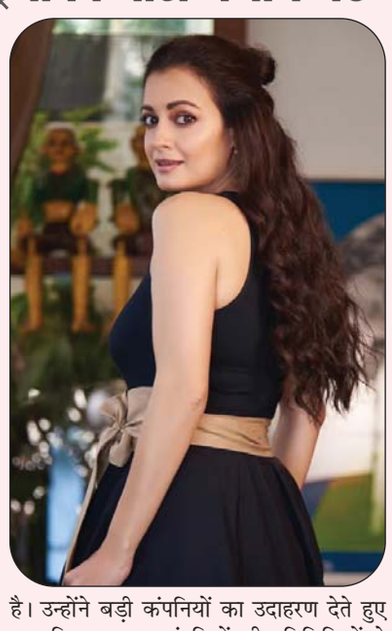

है। उन्होंने बड़ी कंपनियों का उदाहरण देते हुए पूछा कि जब कुछ कंपनियों की गतिविधियों से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है, तो आखिर उन्हें इसके बावजूद बच निकलने का मौका कैसे मिलता है।

'मैं किसी की बेइज्जती नहीं करूंगी'

ट्रोलिंग पर बात करते हुए दीया ने कहा कि वह अपमानजनक भाषा का जवाब उसी अंदाज में नहीं देना चाहतीं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ट्रोल्स अक्सर घटिया और खतरनाक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो किसी की बेइज्जती नहीं करेंगी, भले ही सामने वाला उनकी बेइज्जती कर रहा हो।

दीया ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर कई बार एक जैसे कमेंट्स और कॉपी-पेस्ट कंटेंट दिखाई देते हैं। दीया मिर्जा लंबे समय से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखती रही हैं। इस इंटरव्यू में भी उन्होंने अपने बयान को पुरुषों के खिलाफ किसी व्यक्तिगत सोच के बजाय पर्यावरण, बराबरी और संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़े नजरिए के तौर पर समझाया।

उनका कहना है कि पेट्रियार्की को क्लाइमेट चेंज से जोड़ने की बात का मकसद पुरुषों को निशाना बनाना नहीं, बल्कि उस व्यवस्था और सोच पर सवाल उठाना है, जो उनके अनुसार शोषण और संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल को सामान्य बनाती है।

'टॉक्सिक' के लिए थिएटर्स में तैयारियां शुरू

गीतू मोहनदास की फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इसके साथ ही मंबई और बंगलूरू में टिकट की कीमतों में इजाफा देखा गया है। वहीं दर्शकों की भारी मांग को देखते हुए अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट शो टाइम भी जोड़े गए हैं।

साउथ सुपरस्टर यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स' की रिलीज को अब सिर्फ दो दिन बचे हैं। 26 अगस्त को यह फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की मांग को देखते हुए मुंबई और बंगलूरू के थिएटर्स ओनर्स ने भी इसे लेकर खास तैयारियां की हैं। सभी जगह शोज टाइम और टिकट रेट को लेकर हलचल शुरू हो गई है।

यश की फिल्म 'टॉक्सिक' उन चुनिंदा फिल्मों में से एक बन चुका है जिसका इंतजार ना सिर्फ साउथ बल्कि नॉर्थ इंडिया के दर्शक भी बेसब्री से कर रहे हैं। मुंबई में फिल्म का क्रेज देखते हुए कई सिनेमाघरों फर्स्ट डे फर्स्ट शो सुबह 6 बजे ही शुरू किया गया है। वहीं कुछ जगहों पर यह फिल्म सुबह 7 बजे के शोज में भी दिखाई जाएगी। इसके अलावा लेट नाइट शोज में भी काफी बदलाव किए गए हैं। कुछ सिनेमाघरों में आखिरी शो रात 11.45 तक का है। वहीं बंगलूरू में कई जगहों पर इसे सुबह 3 बजे भी प्रदर्शित किया जाएगा।

मुंबई में टिकटों की कीमत 2000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। बांद्रा स्थित जियो वर्ल्ड ड्राइव में, 'टॉक्सिक' के लिए सबसे महंगी टिकट की कीमत 2,250 रुपये बताई जा रही है। वहीं बेंगलुरु में, फेरम रेक्स वॉक में प्रीमियम टिकटों की कीमत 2,181 रुपये तक बताई जा रही है।

मुंबई और बेंगलुरु के कई अन्य मल्टीप्लेक्स में भी 1,500 रुपये से अधिक कीमत के टिकट बिक रहे हैं। टिकटों के बढ़ती कीमत को देख इस फिल्म की पॉपुलरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है।

'ये बहुत शर्मनाक है', रक्षा बंधन के विज्ञापन में अपने ब्लाउज को लेकर ट्रोल हुई कृति सेनन, लोगों ने सुनाई खरी-खोटी

बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन इन दिनों एक ज्वेलरी ब्रांड के रक्षाबंधन विज्ञापन को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना कर रही हैं। विज्ञापन में कृति का पारंपरिक अंदाज तो नजर आया, लेकिन उनके कपड़ों और विज्ञापन की थीम को लेकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने आपत्ति जताई। देखते ही देखते ये एड सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया।

रक्षाबंधन के विज्ञापन में दिखा कृति का अलग अंदाज

दरअसल, रक्षाबंधन के मौके पर एक विज्ञापन में कृति सेनन नजर आ रही हैं। विज्ञापन में अभिनेत्री ने ऑफ-व्हाइट रंग का ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज, केप और ड्रेप्ड स्कर्ट पहनी हुई है। उनका लुक मॉडर्न और पारंपरिक स्टाइल का मिश्रण दिखाई देता है।

कृति के कपड़ों पर यूजर्स ने जताई नाराजगी

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कृति सेनन के पहनावे को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। कुछ यूजर्स ने इसे भारतीय त्योहारों की भावनाओं से जोड़ते हुए विज्ञापन की आलोचना की। वहीं, कुछ लोगों ने ब्रांड से सवाल किया कि रक्षाबंधन जैसे त्योहार को दिखाने के लिए इस तरह की थीम और स्टाइलिंग की जरूरत क्यों पड़ी।

एक यूजर ने विज्ञापन को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं, दूसरे यूजर्स ने भी कृति के लुक पर सवाल उठाते हुए कहा कि विज्ञापन में पारंपरिक रक्षाबंधन की झलक कम और आधुनिक फैशन पर ज्यादा जोर नजर आ रहा है।

कुत्ते को राखी बांधने पर भी उठे सवाल

सिर्फ कृति का आउटफिट ही नहीं, बल्कि विज्ञापन में दिखाई गई एक दूसरी चीज भी लोगों को पसंद नहीं आई। विज्ञापन में कृति एक कुत्ते को राखी बांधती नजर आती हैं। इस सीन का मकसद पालतू जानवर को परिवार का हिस्सा दिखाना हो सकता है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे रक्षाबंधन की परंपरा से जोड़कर सवाल खड़े किए।

कुछ लोगों का कहना है कि विज्ञापन निर्माताओं ने त्योहार को अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयोग सभी को पसंद नहीं आया। इसी वजह से सोशल मीडिया पर विज्ञापन को लेकर बहस शुरू हो गई।

कृति सेनन ने नहीं दिया कोई जवाब

विवाद बढ़ने के बावजूद कृति सेनन की तरफ से अब तक इस आलोचना पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अभिनेत्री के प्रशंसकों का एक वर्ग उनके समर्थन में भी नजर आ रहा है, जबकि कुछ यूजर्स लगातार विज्ञापन और उनके लुक की आलोचना कर रहे हैं।

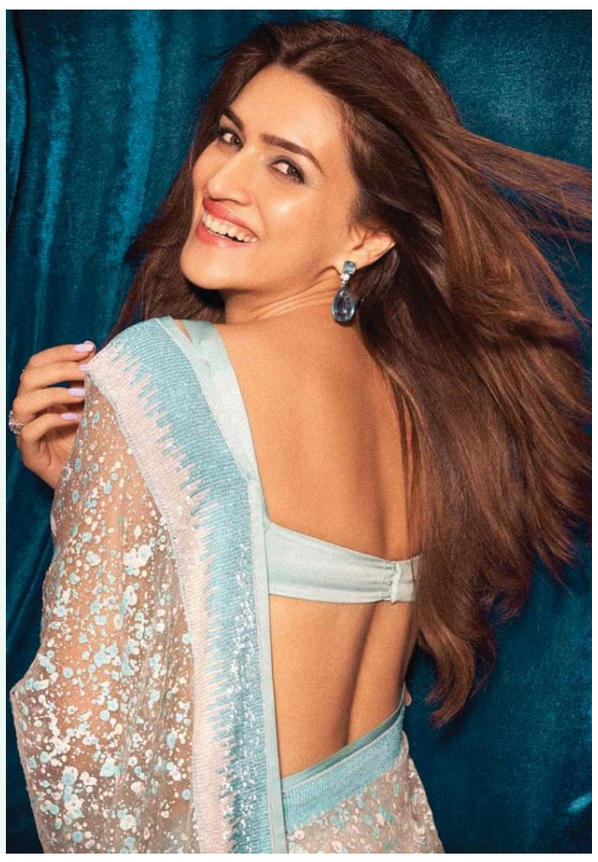

रक्षाबंधन पर जमकर मिठाई खाने से पहले पढ़ लें ये हेल्थ टिप्स, सेहत रहेगी दुरुस्त

रक्षाबंधन ऐसा त्योहार है, जिसमें लोग खूब बढ़-चढ़कर मिठाई खाते हैं। पर, आजकल बाजार में मिलावट वाली मिठाई मिलती है। ऐसे में मिठाई खाते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। रक्षाबंधन पर भाई-बहन के रिश्ते में मिठास घोलने के लिए मिठाई खिलाने की परंपरा है। त्योहार आते ही घर में लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और दूसरी मिठाइयां खूब आती हैं। लेकिन स्वाद के साथ सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है।

बाजार में लंबे समय से रखी मिठाई आपकी तबीयत खराब कर सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि रक्षाबंधन पर मिठाई खाते समय किन बातों का ध्यान रखें? कौन-सी मिठाई जल्दी खराब हो सकती है और खाने से पहले उसकी ताजगी कैसे पहचानें? डायबिटीज या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को कितना मीठा खाना चाहिए? इस लेख में आपके ऐसे ही सवालों के जवाब हम देंगे।

मिलावटी मिठाई से सेहत को क्या नुकसान हो सकता है?

त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ने पर मिलावट या खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों का जोखिम बढ़ सकता है। दूषित या खराब मिठाई खाने से पेट दर्द, उल्टी, दस्त और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या हो सकती है। खासकर दूध, खोया, छेना और क्रीम से बनी मिठाइयों को सही तापमान पर रखना जरूरी होता है। इसलिए ऐसी जगह से ही मिठाई खरीदें, जहां आपको भरोसा हो कि मिलावट नहीं मिलेगी।

ज्यादा मिठाई खाने से बढ़ सकती है परेशानी

मिठाइयों में आमतौर पर शुगर और कैलोरी अधिक होती है। एक साथ बहुत ज्यादा मिठाई खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है। डायबिटीज वाले लोगों के लिए खासतौर पर मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा ज्यादा मीठा खाना लंबे समय में वजन बढ़ने और दांतों की समस्याओं से भी जुड़ा हो सकता है।

मिठाई खाने से पहले इन संकेतों पर दें ध्यान

मिठाई खरीदते समय उसके रंग, गंध और बनावट को जरूर देखें। अगर उसमें असामान्य गंध आ रही है, रंग जरूरत से ज्यादा तेज है, मिठाई चिपचिपी है या उसका स्वाद सामान्य नहीं लग रहा, तो उसे खाने से बचें। पैक्ड मिठाई खरीद रहे हैं तो पैकेट की सील, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी/बेस्ट-बिफोर जानकारी भी जांचें।

दूध और खोये की मिठाई में रखें ज्यादा सावधानी

दूध, खोया, छेना और क्रीम वाली मिठाइयां जल्दी खराब हो सकती हैं। इन्हें खरीदने के बाद बहुत देर तक कमरे के तापमान पर रखने से बचें और पैकेज पर दिए स्टोरेज निर्देशों का पालन करें। गर्म मौसम में यह सावधानी और भी जरूरी हो जाती है।

कितनी मिठाई खाना सही है?

त्योहार पर मिठाई पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन मात्रा कंट्रोल सबसे महत्वपूर्ण है। एक साथ कई तरह की मिठाइयां खाने के बजाय छोटी मात्रा लें। मिठाई के साथ मीठे पेय लेने से बचना भी कुल शुगर और कैलोरी का सेवन कम रखने में मदद कर सकता है।

इन लोगों को खास सावधानी रखनी चाहिए

डायबिटीज, मोटापा या ब्लड शुगर से जुड़ी समस्या वाले लोगों को मिठाई की मात्रा को लेकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बच्चों को भी जरूरत से ज्यादा मिठाई देने से बचें। अगर खराब मिठाई खाने के बाद लगातार उल्टी, दस्त, तेज पेट दर्द, बुखार या कमजोरी जैसे लक्षण हों, तो चिकित्सकीय सलाह लेना बेहतर है।

'बर्बाद करने के लिए कुछ भी करते हैं', तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड को लेकर किया नया दावा

बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट शेयर करते हुए फिल्म इंडस्ट्री के कुछ वरिष्ठ कलाकारों को लेकर तीखी टिप्पणी की है। हालांकि तनुश्री ने अपनी पोस्ट में किसी अभिनेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने 'वेटरन' कहे जाने वाले कुछ लोगों के व्यवहार पर सवाल जरूर खड़े किए हैं।

तनुश्री ने कहा कि किसी व्यक्ति की उम्र उसके चरित्र या सम्मान का पैमाना नहीं हो सकती। उनके मुताबिक, अब उन्होंने लोगों को उनकी उम्र के बजाय उनके स्वभाव और चरित्र के आधार पर परखना सीख लिया है। अभिनेत्री की इस पोस्ट के बाद बॉलीवुड में एक बार फिर उनके बयान को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

'वेटरन' शब्द को लेकर तनुश्री ने कही बड़ी बात

तनुश्री दत्ता ने अपने पोस्ट में एक पुराने अनुभव का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एक समय उन्हें लगा था कि कोई उम्रदराज अभिनेता इंडस्ट्री में काम न मिलने के कारण मुश्किल दौर से गुजर रहा है और उन्हें मदद की जरूरत है। इसी सोच के साथ वह उनकी सहायता करना चाहती थीं।

लेकिन बाद में अभिनेत्री के मुताबिक उनका नजरिया बदल गया। उन्होंने 'वेटरन' शब्द की अपनी अलग व्याख्या करते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में कई साल गुजारने वाले कुछ लोग सिर्फ अनुभवी ही नहीं होते, बल्कि इंडस्ट्री के तौर-तरीकों और लोगों की सोच को प्रभावित करने में भी माहिर हो जाते हैं।

तनुश्री ने अपने पोस्ट में ऐसे लोगों के लिए 'शातिर-दिमाग मंजा हुआ खिलाड़ी' जैसी टिप्पणी का इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि किसी को केवल उम्र या लंबे करियर की वजह से अपने आप सम्मान का हकदार नहीं मान लेना चाहिए।

तनुश्री ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इंडस्ट्री में युवा और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के प्रति कथित नकारात्मक रवैये का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि कुछ वरिष्ठ और नकारात्मक सोच रखने वाले लोग युवा लोगों को पसंद नहीं करते और उन्हें आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते।

अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि ऐसे लोगों के मन में युवाओं के प्रति इतनी नकारात्मकता हो सकती है कि वे उन्हें नुकसान पहुंचाने या उनका करियर प्रभावित करने की कोशिश तक कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपने इस दावे के समर्थन में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया और न ही किसी खास घटना का विवरण दिया। तनुश्री की पोस्ट की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने किसी एक अभिनेता को सीधे तौर पर निशाना नहीं बनाया। उन्होंने अपनी बात को सामान्य रूप में रखा और फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद एक कथित मानसिकता पर सवाल उठाया। हालांकि, बिना किसी नाम या स्पष्ट संदर्भ के यह कहना मुश्किल है कि तनुश्री का निशाना कौन था। ऐसे में उनकी पोस्ट के आधार पर किसी खास अभिनेता के बारे में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

फिलहाल उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में है और लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अभिनेत्री के इस तीखे बयान के पीछे आखिर कौन सा अनुभव है। लेकिन जब तक तनुश्री खुद किसी व्यक्ति या घटना का स्पष्ट उल्लेख नहीं करतीं, तब तक उनके बयान को किसी खास अभिनेता से जोड़ना महज अटकल ही माना जाएगा।

खास-खबर

उप मुख्यमंत्री साव ने बाबाघाट धाम में किया रुद्राभिषेक

रायपुर। लोरमी के श्री बाबाघाट धाम में पावन श्रावण मास के अंतिम सोमवार को आस्था और विकास का सुंदर संगम देखने को मिला। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमीवासियों के साथ परम पूज्य श्री श्री 108 शिवानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में भगवान भोलेनाथ का विधिवत रुद्राभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने महादेव से सभी के सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। रुद्राभिषेक के बाद श्री साव ने मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण एवं उन्नयन कार्यों का लोकार्पण किया। भंडारे में श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया। उन्होंने कहा कि 'विरासत भी, विकास भी' की सोच के साथ लोरमी की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का कार्य किया जा रहा है। सौंदर्यीकरण के बाद बाबाघाट का स्वरूप भव्य और आकर्षक हुआ है। श्रद्धालुओं को यहां स्वच्छ, शांत और भक्तिमय वातावरण मिलेगा। श्री साव ने कहा कि श्री बाबाघाट धाम लोरमी का प्राचीन धार्मिक स्थल है। वर्षों से यहां साधु-संत पूजन, हवन एवं विश्राम करते रहे हैं। समय के साथ यह स्थल जीर्ण-शीर्ण हो गया था। अब इसके सौंदर्यीकरण और उन्नयन से नया स्वरूप मिला है।

ग्रामीणों के साथ जमीन में बैठकर जिला पंचायत सीईओ ने सुनी मन की बात

कोरिया। कलेक्टर कोरिया रोक्तिमा यादव के निर्देशन में प्रत्येक योजना का पात्र हितग्राहियों तक पारदर्शिता से लाभ पहुंचाने के लिए जिले के अधिकारी निरंतर क्षेत्र भ्रमण कर हितग्राहियों से सीधा संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में गत दिवस जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी योगेन्द्र श्रीवास ने बैकुंठपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पटमा एवं ग्राम पंचायत गढ़तर पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से मुलाकात की और जमीन पर बैठकर आम ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। जनचौपाल में सभी से संवाद कर उनकी आवश्यकताओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। साथ ही भ्रमण में उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना की जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत की टीम उपस्थित रही। जिला पंचायत सीईओ योगेन्द्र श्रीवास ने ग्राम पंचायतों में पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राहियों के नवनिर्मित आवासों का निरीक्षण किया। इस दौरान पक्के आवास से बढ़ी सहूलियत पर हितग्राहियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। ग्राम पंचायतों में निरीक्षण के दौरान हितग्राहियों से सीधे संवाद कर आवास निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता एवं योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी ली गई।

एग्रीस्टेक पंजीयन के लिए लगाए शिविर - कलेक्टर तनुजा सलाम

श्रीकंचनपथ समाचार

मोहला। कलेक्टर तनुजा सलाम ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्य प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर मिथलेश डोंडे, एसडीएम मोहला हेमेंद्र भुआर्य, एसडीएम मानपुर अमित नाथ योगी, डिप्टी सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर सलाम ने एग्रीस्टेक पंजीयन की समीक्षा करते हुए कहा कि अधिक से अधिक किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विशेष शिविर लगाए जाएं। उन्होंने किसानों को एग्रीस्टेक पंजीयन के महत्व की जानकारी देते हुए जागरूक करने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी किसान पंजीयन से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि एग्रीस्टेक पंजीयन होने से किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी।कलेक्टर ने स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि बेहतर प्रगति के लिए अधिकारी एवं कर्मचारी बेहतर कार्ययोजना बनाकर कार्य करें। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सलाम ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि जनसामान्य की सुविधा के लिहाज से राजस्व से जुड़े कार्य हमारी प्राथमिकता हैं। राजस्व से संबंधित सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अविवादित खाता विभाजन, विवादित खाता विभाजन, अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण, नक्शा बटांकन एवं डायवर्सन सहित विभिन्न राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार लंबे समय से लंबित प्रकरणों का अतिशीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पटवारियों की बैठक लेकर उनके स्तर पर लंबित कार्यों के निराकरण के निर्देश भी दिए।

डिजिटल क्रॉप सर्वे की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने कहा कि सर्वे कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाए, ताकि सर्वे का कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण हो सके। इस दौरान उन्होंने निस्तार पत्रक अंतर्गत आस्था केंद्र की समीक्षा करते हुए शेष कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

ईडब्ल्यूएस भूमि के बिना प्लाटिंग पर कॉलोनाइजरों के विरुद्ध होगी कार्रवाई

बारिश से प्रभावित स्कूल-छात्रावास मार्गों का होगा चिन्हांकन, दुर्घटना पीड़ितों को उपचार में निर्धारित योजना का लाभ दिलाने के निर्देश

श्रीकंचनपथ समाचार

रायगढ़। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस के लिए भूमि चिन्हांकित किए बिना प्लाटिंग करने वाले कॉलोनाइजरों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा कॉलोनाइजरों से निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। जिला कलेक्टोरेट में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभागवार लंबित प्रकरणों एवं शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में मैदानी स्तर पर प्रभावी परिणाम लाने और पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया।

कलेक्टर ने बारिश से प्रभावित स्कूल, आश्रम एवं छात्रावासों तक पहुंचने वाले सड़क मार्गों तथा पुल-पुलियों का चिन्हांकन कर सूची तैयार करने और खनन प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे आवश्यक कार्यों को डीएमएफ से स्वीकृत कराने के लिए भी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध अतिक्रमण एवं दूसरे की भूमि पर कब्जे से संबंधित शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई करें। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की समीक्षा करते हुए ऐसे हितग्राहियों जिनके खातों में आवास निर्माण की राशि पहुंच चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, उनका आवास निर्माण शीघ्र शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण में रुचि नहीं लेने वाले हितग्राहियों की राशि नियमानुसार राशि वसूली की कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने कृषक उन्नति योजना के तहत धान के स्थान पर अन्य फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए निर्धारित लक्ष्य एवं प्रगति और पीएम आशा योजना के तहत जिले में आठ नए केंद्रों के लिए भेजे गए प्रस्ताव की जानकारी ली।

कलेक्टर ने जिले के स्कूलों, छात्रावासों एवं आश्रमों का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों की प्रगति, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सर्वे की भी समीक्षा की। उन्होंने जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी लेते हुए नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं नशीली औषधियों एवं अवैध शराब के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करते हुए नियमानुसार कार्रवाई जारी रखने को कहा।

कलेक्टर ने पशुपालकों को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक पशु दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला एवं विकासखंड स्तर पर पशु औषधि विक्रय केंद्र स्थापित किए जाने की प्रक्रिया की जानकारी ली। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र एवं सहकारी समितियों के माध्यम से केंद्र स्थापित करने की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए।

बाल अधिकारों की सुरक्षा और साइबर अपराध से बचाव को लेकर धनोरा में विधिक जागरूकता शिविर

श्रीकंचनपथ समाचार

कोण्डागांव। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव सुश्री गायत्री साय व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल श्रीमती सौम्या राय के नेतृत्व में सरस्वती शिशु मंदिर धनोरा* में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना तथा बाल संरक्षण, साइबर सुरक्षा, यातायात नियमों एवं निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी प्रदान करना रहा। कार्यक्रम में अधिकार मित्र द्वारा विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम, 2012, बाल अपराधों से बचाव एवं बच्चों के अधिकारों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही यातायात नियमों का पालन, सड़क सुरक्षा, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के उपयोग तथा नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने के संबंध में जागरूक किया गया।

इसके अलावा विद्यार्थियों को साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने, ह्यक्र एवं पासवर्ड किसी के साथ साझा नहीं करने तथा सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया एवं नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं आपातकालीन हेल्पलाइन 112 के संबंध में भी जानकारी दी गई।

बालिकाओं की सुरक्षा और अधिकारों पर विशेष जोर, चिचाड़ी में विधिक जागरूकता शिविर

श्रीकंचनपथ समाचार

कोण्डागांव। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव सुश्री गायत्री साय के नेतृत्व में शासकीय एकलव्य बालिका छात्रावास चिचाड़ी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में अधिकार मित्र धनवती कोर्राम द्वारा छात्रावास की बालिकाओं को विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बालिकाओं को बाल अधिकार, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल संरक्षण संबंधी कानून, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम , गुड टच-बैड टच, साइबर अपराध तथा ऑनलाइन ठगी से बचाव सहित विभिन्न विषयों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी। अधिकार मित्र द्वारा बालिकाओं को किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न अथवा अपराध की स्थिति में चुप न रहने तथा इसकी जानकारी तत्काल अपने अभिभावक, शिक्षक अथवा संबंधित अधिकारियों को देने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली विधिक सेवाओं के संबंध में भी जानकारी दी गई। शिविर का उद्देश्य छात्राओं में उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा उन्हें किसी भी विपरीत परिस्थिति में कानून की सहायता लेने के लिए सक्षम एवं जागरूक बनाना रहा। प्राधिकरण कोण्डागांव द्वारा जिले के विभिन्न विद्यालयों, छात्रावासों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के विधिक जागरूकता कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि आमजन विशेषकर बच्चों एवं महिलाओं को उनके अधिकारों और कानून के प्रति जागरूक किया जा सके।

जांजगीर-चांपा के शासकीय स्कूलों में बनेंगे 79 बालिका शौचालय

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में 'मेरी बेटी-मेरा अभिमान' अभियान के माध्यम से बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए मूलभूत सुविधाओं के विस्तार को गति दी जा रही है। इसी क्रम में जांजगीर-चांपा जिले के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की सुविधा के लिए 79 बालिका शौचालय निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रत्येक शौचालय के निर्माण के लिए 4.30 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

स्वीकृत इन कार्यों को विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) योजना के तहत विद्यालयों की आवश्यकता और छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है।

स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण से बढ़ेगा छात्राओं का आत्मविश्वास विद्यालयों में पृथक एवं उपयोगी शौचालय की सुविधा केवल स्वच्छता से जुड़ी आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह बालिकाओं की नियमित उपस्थिति, सुविधा, गरिमा और आत्मविश्वास से भी सीधे जुड़ी है। नए शौचालयों के निर्माण से छात्राओं को विद्यालय परिसर में बेहतर स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध होंगी और उनके लिए सुरक्षित एवं अनुकूल शैक्षणिक वातावरण तैयार होगा।

जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय विद्यालयों में आवश्यक अधोसंरचना एवं मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विद्यालयों में बालिका शौचालय के साथ विद्यार्थियों एवं ग्रामीण समुदाय को सीधे लाभ पहुंचाने वाले अन्य आवश्यकता आधारित कार्यों को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

अधिकारियों को स्वीकृत कार्यों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध रूप से प्रारंभ करने तथा निर्माण में गुणवत्ता, उपयोगिता और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की नियमित समीक्षा कर आवश्यकता के अनुसार नए कार्यों के प्रस्ताव भी तैयार किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन का प्रयास है कि जिन शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए पर्याप्त शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर इस सुविधा से जोड़ा जाए। विद्यालय में स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय की उपलब्धता छात्राओं की नियमित उपस्थिति और शिक्षा की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है। 79 बालिका शौचालयों की स्वीकृति इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे छात्राओं को विद्यालय में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने ई-बस योजना पीएम आवास और वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजना की समीक्षा की

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री ई-बस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत प्रस्तावित वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजना तथा 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।

उन्होंने योजनाओं की व्यवहारिकता, वित्तीय पक्ष, समयबद्ध क्रियान्वयन तथा नागरिकों को मिलने वाले लाभों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने इन योजनाओं के क्रियान्वयन में जनसुविधा, समग्र योजना, समयबद्धता, वित्तीय व्यवहार्यता और दीर्घकालिक स्थिरता को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की समय-सीमा में पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुमित अग्रवाल भी बैठक में मौजूद थे।

प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बैठक में प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत रायपुर में ई-बसों के संचालन को व्यवस्थित, सुविधाजनक और अधिक जनोपयोगी बनाने के लिए व्यापक रूट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-बसों के रूट निर्धारित करते समय रायपुर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के साथ स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को शामिल करें, ताकि शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके और अधिक से अधिक नागरिक सार्वजनिक परिवहन का लाभ उठा सकें। उन्होंने प्रस्तावित बस रूटों की व्यवहारिकता, यात्री आवागमन एवं कनेक्टिविटी का आकलन करने के लिए विस्तृत सर्वे प्लान तैयार कराने के निर्देश दिए। साथ ही पीपीपी मॉडल के आधार पर बस-स्टॉप्स की सूची तैयार करने तथा बस-स्टॉप्स का निर्धारण यात्रियों की सुविधा और आवश्यकता के अनुरूप करने को कहा।

प्रमुख सचिव ने यात्रियों की सुविधा और आम नागरिकों की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत एवं सुविधाजनक किराया निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-बस योजना को आधुनिक एवं नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए नवीन तकनीकों का प्रभावी उपयोग किया जाए। बस-रूट, बस-स्टॉप, बसों की उपलब्धता एवं यात्री सुविधाओं से संबंधित व्यवस्थाओं को तकनीक आधारित बनाते हुए ऐसी कार्ययोजना तैयार की जाए, जिससे यात्रियों को सुगम, सुरक्षित और बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सके।

श्री बोरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों को मिशन अवधि की अंतिम निर्धारित तिथि 30 सितम्बर 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय निकायों में शेष एवं निर्माणाधीन आवासों की संख्या के आधार पर साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित कर विशेष ड्राइव चलाने तथा आवास निर्माण को मिशन मोड में पूर्ण करने को कहा। उन्होंने प्रत्येक नगरीय निकाय स्तर पर आवासों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने और जहां निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है, वहां आवश्यक समन्वय कर कार्यों में तेजी लाने को कहा।

प्रमुख सचिव ने जिला कलेक्टरों को भी जिले में शेष आवासों को पूर्ण कराने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने तथा उनकी सतत समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन एवं नगरीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लंबित आवासों को समय-सीमा में पूर्ण कराया जाए। उन्होंने हितग्राहियों के आवास निर्माण की वास्तविक प्रगति के आधार पर योजना के प्रावधानों के अनुसार किस्त की राशि का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि हितग्राहियों को आवश्यक वित्तीय सहायता मिल सके और निर्माण कार्य में गति बनी रहे।

महतारी वंदन योजना से नारायणपुर जिले की 27,272 महिलाओं को मिल रहा आर्थिक संबल

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं के बैंक खातों में प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे डीबीटी के माध्यम से जमा की जा रही है। इससे महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ने के साथ परिवार की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिल रही है। नारायणपुर जिले में योजना के प्रथम चरण में 26,710 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है, जबकि द्वितीय चरण में नियद नेल्लानार के अंतर्गत 562 हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल रहा है।

CAR DECOR
House Of Exclusive Seat Cover, Car Stereos Matting & Sun Control Film & Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower. Opp. Indian Coffee House, Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

ॐ SAIRAM Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़कों की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden) Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्टेक्स एवं ग्रहरत्न उपलब्ध यहां उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles, CPVC Pipes & Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

भारी बारिश में आत्मानंद स्कूल की फॉल सीलिंग गिरी

बिलासपुर। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में तेज बारिश के दौरान बड़ा हादसा हो गया। स्कूल के चार कमरों की फॉल सीलिंग अचानक भरभराकर नीचे गिर गई। हादसे के वक्त स्कूल में छात्र और शिक्षक मौजूद नहीं थे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हादसे में प्रिंसिपल ऑफिस, छठवीं कक्षा और कंप्यूटर रूम समेत कुल चार कमरों की फॉल सीलिंग गिरने की जानकारी सामने आई है। हादसा रात के समय हुआ, इसलिए किसी छात्र या शिक्षक के इसकी चपेट में आने की सूचना नहीं है।

सूरजपुर जिले में एक ही फंदे पर झूला प्रेमी जोड़ा

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में प्रेमी जोड़े ने एक ही फंदे पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मामला लटोरी चौकी क्षेत्र का है। मंगलवार को ग्रामीणों ने कोटबहरा जंगल की ओर जाते समय पेड़ से लटकते हुए दो शवों को देखा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस दोनों शवों को फंदे से उतारकर पंचनामा कर रही है। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा।

चोरी के 7 मामलों का खुलासा; 12 लाख का माल बरामद

रायपुर। रक्षाबंधन पर बाजार में भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं और बच्चों के गले से सोने-चांदी के आभूषण चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। एसीसीयू और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरोह की दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शहर के अलग-अलग भीड़भाड़ वाले इलाकों में चोरी की 7 वारदातें करना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 12 लाख रुपए के सोने-चांदी के आभूषण और अन्य सामान बरामद किया है। आरोपियों की पहचान नंदनी राजपूत और सानिया मरकाम के रूप में हुई है।

जान से भी मारने की धमकी देकर बाइक लूट, गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी रायपुर में पुरानी रंजिश के चलते युवक से मारपीट कर दोपहिया वाहन लूटने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने युवक को घेरकर गाली-गलौज की और मारपीट करने के बाद जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसकी बाइक लेकर मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राज मिश्रा, यश मिश्रा उर्फ रोहन मिश्रा और अभिषेक पटेल के रूप में हुई है।

साधु बनकर गांजा तस्करी करते दो गिरफ्तार

बिलासपुर। रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन 'नारकोस' के तहत निगौरा रेलवे स्टेशन पर साधु के भेष में गांजा ले जा रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 15.540 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत 7.77 लाख रुपए है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पंजाब के संगरूर जिले के हंसा नाथ (40) और मनता नाथ उर्फ लंबू (39) के रूप में हुई है।

बाघिन ने ले ली युवक की जान, करील बीनने गया था बांधा जंगल, वन विभाग ने जारी की एडवाइजरी

श्रीकंचनपथ समाचार

बिलासपुर। बांधा गांव में जंगल गए 25 वर्षीय धरम दास घृतलहरे पर बाघिन ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। बाघिन शावक के साथ क्षेत्र में मौजूद है। वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल न जाने की चेतावनी दी है।

घटना जोगीपुर फॉरेस्ट के कंपार्टमेंट नंबर 98 आरएफके पास की बताई जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार, धरम दास सोमवार सुबह करीब साढ़े 7 बजे जंगल में बांस का करिल और मशरूम बीनने गया था। इसी दौरान घात लगाकर बैठी बाघिन ने उस पर हमला कर दिया। बाघिन ने युवक की गर्दन पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमले के बाद बाघिन ने शव को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।

बताया जा रहा है कि घटनास्थल के आसपास बाघिन अपने शावक के साथ

विचरण कर रही है। बाघिन और उसके शावक की मौजूदगी से आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने और सतर्क रहने की हिदायत दी है।

ग्राम बांधा और आसपास का जंगल क्षेत्र कीमती इमारती लकड़ियों की अवैध कटाई और तस्करी के लिए भी लंबे समय से चर्चा में रहा है। जंगल में लकड़ी तस्करों और ग्रामीणों की लगातार आवाजाही के कारण मानव और वन्यजीवों के आमने-सामने आने का खतरा बना रहता है।

तखतपुर थाना प्रभारी अवनीश पासवान ने फोन पर बताया कि सूचना मिलने के बाद जुनापारा पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। युवक की मौत बाघिन के हमले से ही हुई है। पंचनामा की कार्रवाई कर मामले की जांच की जा रही है।

ग्राम हेमाबंद में गौवंशों की मौत का मामला गहराया, आरोपी पिता-पुत्र को भेजा गया जेल

बिना दाना-चारा के भूख-प्यास से बीमार बूढ़ी गायों की मौत

श्रीकंचनपथ समाचार

बेमेतरा। जिले के हेमाबंद गांव में गौवंशों की मौत के मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप है कि आरोपी पैसे लेकर गौवंशों को गांव की सीमा के पास छोड़कर रखता था, जहां पर्याप्त चारे और पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण कई पशुओं की मौत हो गई।

घटना की जानकारी सामने आने के बाद मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची। जांच के दौरान कई गौवंश मृत मिले, जबकि बड़ी संख्या में पशु बीमार और कमजोर हालत में पाए गए। प्रारंभिक तौर पर पशुओं की स्थिति के पीछे चारा-पानी की कमी को प्रमुख वजह माना जा रहा है।

जिला प्रशासन ने मौके से 126 जीवित गौवंशों को सुरक्षित निकालकर अलग-अलग गौशालाओं में पहुंचाया है, ताकि उनका उपचार और देखभाल की जा सके। वहीं मृत पशुओं की वास्तविक मौत की वजह स्पष्ट करने के लिए प्रशासन ने तीन पशु चिकित्सकों की टीम गठित की है।

गौवंशों की बदहाल स्थिति और मौत की जानकारी सामने आने के बाद गौसेवकों ने मामले को लेकर विरोध जताया। इसके बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया है। अब पशु चिकित्सा टीम की जांच रिपोर्ट के बाद मृत गौवंशों की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा होने की उम्मीद है।

कोरबा में सोशल मीडिया पर गौमाता को लेकर किये गये कमेंट से बवाल

कोरबा के उरगा थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर गौ माता को लेकर किए गए कमेंट के बाद युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और गौ सेवा रक्षक टीम के सदस्यों के बीच विवाद हो गया। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। दोनों पक्ष शिकायत लेकर थाने पहुंचे, जबकि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया पर गौ माता को लेकर किसी पोस्ट पर कमेंट किया गया था, जिसको लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और गौ सेवा रक्षक टीम के सदस्यों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद गहरा गया और दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर मारपीट होने की बात सामने आई है।

मारपीट की घटना के बाद दोनों ही पक्ष शिकायत दर्ज कराने के लिए उरगा थाने पहुंचे। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इस घटना के बाद कड़ी कार्रवाई और आरोपियों पर धाराएं बढ़ाने की मांग को लेकर थाना परिसर के सामने ही धरने पर बैठ गए। युवा कांग्रेस नेता मधुसूदन अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। काफी देर तक दोनों पक्ष थाने में ही डटे रहे, जिससे थाने में तनाव का माहौल बन गया। विवाद बढ़ता देख उरगा थाना पुलिस ने मामला शांत करने का प्रयास किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश दी और माहौल को नियंत्रित किया।

इस पूरे मामले में उरगा थाना प्रभारी नवीन पटेल ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है। दोनों पक्षों की शिकायत पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आगे जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट की भी जांच की जा रही है। वहीं, युवा कांग्रेस कार्यकर्ता थाने के सामने प्रदर्शन कर न्याय की मांग कर रहे हैं।

इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार हुई बैंक मैनेजर, ट्रांसफर कर दिए 5 लाख

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। भारतीय स्टेट बैंक की आईजीकेवी शाखा की मैनेजर ठगी का शिकार हो गई। आरोपी ने मेडिकल बिल के भुगतान के बहाने उनसे 5 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया। उसने खुद को एक कार कंपनी के संचालक बता कर मैनेजर को विश्वास में लिया था।

बैंक मैनेजर श्वेता शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात मोबाइल नंबर धारक के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत केस दर्ज किया है।

पुलिस के मुताबिक, 20 अगस्त को श्वेता शर्मा के मोबाइल पर एक व्यक्ति ने फोन किया। कॉल रिसीव नहीं होने पर उसने मैसेज भेजकर संपर्क किया। आरोपी ने अपना नाम प्रशांत मंधान बताया और खुद को इंटारा कार कंपनी का संचालक बताया।

21 अगस्त को उसने करीब 2 करोड़ रुपए की एफडी कराने की इच्छा जताई और ब्याज दर की जानकारी ली। बैंक मैनेजर ने 6.45 प्रतिशत ब्याज दर बताई। आरोपी ने सोमवार को बैंक आने की बात कही। 24 अगस्त को आरोपी ने फिर संपर्क किया। उसने कहा कि चेकबुक खत्म हो गई है और उसे तत्काल मेडिकल भुगतान करना है। इसके लिए 4 लाख 99 हजार रुपए आरटीजीएस कराने को कहा। बैंक मैनेजर के कहने पर आरोपी ने फर्जी ई-मेल आईडी से भुगतान आवेदन भेज दिया।

दस्तावेज और हस्ताक्षर का मिलान करने के बाद बैंक मैनेजर ने दोपहर करीब 1:20 बजे रकम मुंबई के कुर्ला स्थित केनरा बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी। करीब 40 मिनट बाद संबंधित कंपनी के मैनेजर ने फोन कर बताया कि कंपनी ने ऐसा कोई भुगतान आवेदन नहीं भेजा था।

जांच में मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी भी कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं मिले। इसके बाद फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। अब फोन नंबर के सहारे पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

सोशल मीडिया पर सीएम-डिप्टी सीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग, आईटी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। इंस्टाग्राम पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर अमर्यादित एवं अभद्र भाषा के प्रयोग का मामला सामने आया है। मामले में राष्ट्रवादी विचारक वीरेंद्र दुबे ने सिविल लाइंस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत के अनुसार, इंस्टाग्राम पर 'सागर निर्मलकर' नामक आईडी से एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया गया। साथ ही क्लाइल.3131469 नामक आईडी से कथित तौर पर

अशोभनीय एवं आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने का आरोप है। वीरेंद्र दुबे ने अपनी शिकायत में कहा, संवैधानिक पदों पर आसीन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि इससे सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका भी है।

उन्होंने आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट और संबंधित अकाउंट की गतिविधियों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वीरेंद्र दुबे ने कहा, लोकतंत्र में सरकार और जनप्रतिनिधियों की आलोचना का अधिकार है, लेकिन अभद्र भाषा और गाली-गलौज की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर प्रदेश सरकार और वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है।

पुलिस ने पिकअप सहित जब्त किया 4 टन कबाड़, दो ट्रकों के बीच छिपाकर रखे थे गाड़ी

श्रीकंचनपथ समाचार

दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के भांसी थाना क्षेत्र में पुलिस ने लावारिस पिकअप से करीब 4 टन अवैध लोहे का कबाड़ बरामद किया। कबाड़ की कीमत एक लाख रुपये आंकी गई है। वाहन बचेली से लाया गया था। पुलिस आरोपियों की पहचान और कबाड़ के स्रोत की जांच कर रही है।

भांसी थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस टीम 23 अगस्त को एमसीपी चेकिंग और फॉरेस्ट/खनिज जांच नाका भांसी की ओर गई थी। करीब दोपहर 3 बजे आईडीआई मेन रोड, भांसी बाजारपारा के पास सड़क किनारे दो ट्रकों के बीच एक सफेद रंग की पिकअप लावारिस हालत में खड़ी मिली।

पुलिस टीम ने वाहन की जांच की तो तिरपाल के अंदर भारी मात्रा में लोहे का कबाड़ भरा मिला। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए पिकअप और उसमें भरे कबाड़ को जब्त कर थाना भांसी में सुरक्षित रखवा दिया। मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ में पता चला कि वाहन को बचेली की ओर से लाया गया था। वाहन में सवार लोग खाना खाने जाने की बात कहकर उसे छोड़कर पैदल भांसी-किरंदुल की ओर चले गए थे।

किरंदुल और बचेली क्षेत्र के एनएमडीसी औद्योगिक इलाकों में चोरी और अवैध कबाड़ के कारोबार की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। पुलिस इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पुलिस जब्त कबाड़ के स्रोत और वाहन से जुड़े आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। जांच और कार्रवाई जारी है।

बालाजी गैस एजेंसी पर छापा, 412 सिलेंडर कम मिले

बिलासपुर। बिलासपुर में महाराणा प्रताप चौक स्थित बालाजी गैस एजेंसी पर खाद्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने सुबह छापामार कार्रवाई की। जांच के दौरान ऑनलाइन रिकॉर्ड और मौके पर उपलब्ध स्टॉक में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। रिकॉर्ड के अनुसार एजेंसी में 864 भरे सिलेंडर होने चाहिए थे, जबकि मौके पर सिर्फ 452 भरे सिलेंडर मिले। यानी 412 भरे सिलेंडर कम पाए गए। टीम ने मौके पर मौजूद कुल 939 सिलेंडर जब्त किए, जिनमें 452 भरे और 487 खाली सिलेंडर शामिल हैं। प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए हैं।

धनराज कुंवर अस्पताल के बाथरूम में मानव भ्रूण मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

श्रीकंचनपथ समाचार

कोरबा। पुराने बस स्टैंड के पास स्थित रानी धनराज कुंवर अस्पताल में सोमवार को बाथरूम में मानव भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। अस्पताल कर्मचारियों की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए।

सफाई कर्मी पी. चिना ने बताया कि सोमवार सुबह वह अस्पताल के बाथरूम की सफाई करने पहुंचा था। वहां तेज बदबू आ रही थी। अंदर जाकर देखने पर

उसे भ्रूण पड़ा मिला। उसने तत्काल इसकी जानकारी सुपरवाइजर पवन कुमार साहू को दी।

चिना के मुताबिक, सुपरवाइजर ने उसे भ्रूण को पन्नी में पैक कर छत पर रखने के लिए कहा। उसका कहना है कि उसे यह जानकारी नहीं दी गई कि मामला पुलिस से जुड़ा है और भ्रूण को इस तरह हटाना उचित नहीं है। इसके बाद उसने सुपरवाइजर के कहने पर भ्रूण को पन्नी में पैक कर अस्पताल की छत पर रख दिया।

कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची और पंचनामा कार्रवाई की। सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि मामले में मर्ग कायम किया गया है। भ्रूण का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर आरोपी का पता लगाने की कोशिश की जाएगी।

रिटायर्ड कर्मचारी से ठगी की कोशिश : बिलासपुर में साइबर ठगों ने रिटायर्ड कर्मी को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 35 लाख रुपए की ठगी करने की कोशिश की। ठग ने खुद को आईपीएस अफसर बताकर बुजुर्ग को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने का डर दिखाया। इसके बाद अलग-अलग बैंकों में जमा उनकी रकम एक बैंक खाते में ट्रांसफर कराई गई। हालांकि, समय रहते बिलासपुर पुलिस को इसकी सूचना मिल गई और करीब 35 लाख रुपए की रकम ठगी का शिकार होने से बच गई।

नगरनार में 24.5 किलो गांजा जब्त, आरोपी भेजे गए जेल; ओडिशा से लेकर आए थे खेप

जगदलपुर। नगरनार पुलिस ने फारेस्ट नाका धनपुंजी के पास बस का इंतजार कर रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उनके कब्जे से 24.545 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 12.27 लाख रुपये है। नगरनार थाना प्रभारी ने बताया कि 23 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति थैला, बोरी और बैग में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर फारेस्ट नाका धनपुंजी के पास बस का इंतजार कर रहे हैं। आरोपियों ने अपना नाम चुमन बघेल निवासी ग्राम तुरपुरा, पोड़ाईगुड़ा पारा, थाना भानपुरी और बेनूधर कश्यप निवासी ग्राम कुम्हली, थाना भानपुरी बताया। पुलिस ने जब्त कर लिया है।

भिलाई मसाला उद्योग
शुद्ध कुटे हुए मसाले, पापड़, अचार, बड़ी, जड़ी-बूटी, नचकी का सामान इत्यादि
128, ए- मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई, फोन. 2284508, मो. 9826137766

Ashok JEWELLERY
Gifts • Toys • Cosmetics
Perfumes • Silver Jewellery
Beside Parakh Jewellers, Akash Ganga, Supela, Bhilai
Hello: 0788-4052727
Mukesh Jain 9009959111
Rishabh Jain 8103831329

भिलाई की सबसे बड़ी चुड़ी की दुकान
निखार बैंगल
मो.- 9826186026
Shop-47, 'A' Market, Sec-6, Bhilai Nagar, Distt., Durg (C.G.)

कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बालोद

Phone No.: 07749-222370, Email Id:- ee-res.balod@gov.in

(ई-निविदा (Zonal Tender) सूचना

क्रमांक/11/व.ले.लि./ग्रा.यां.से./2026-27 बालोद, दिनांक 21.08.2026

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत सक्षम श्रेणी के ठेकेदारों से निम्न दर्शित क्षेत्रीय निविदा (Zonal Tender) हेतु जनपद पंचायत (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु) डौण्डीलोहारा ग्रुप (ब) के लिये निविदा हेतु प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर द्वारा दिनांक 01.11.2021 से एवं विद्युतीकरण कार्य हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा दिनांक 01.06.2020 से प्रचलित तथा सिविल कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के दिनांक 20.04.2026 एवं नलकुप खनन हेतु प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रायपुर द्वारा दिनांक 01.06.2020 से प्रभावशील दर अनुसूची की मुद्रित एवं अद्यतन संशोधित दरों पर निविदा प्रतिशत दर पर दिनांक 31.08.2026 तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। अत: अमानत राशि सत्यनिष्ठा संधि एवं तकनीकी दस्तावेज स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक 01.09.2026 को कार्यालयीन समय अपरान्ह 5.30 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 02.09.2026 को 11:30 बजे पूर्वान्ह में खोली जावेगी:-

(1) निविदा राशि रू. 35.00 लाख
(2) अमानत राशि 35000.00
(3) निविदा प्रपत्र का मूल्य :- रू. 1500.00

निविदा दस्तावेज कार्यालय द्वारा विक्रय नहीं किया जावेगा, ऑनलाईन पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in अन्य पोर्टल जिसे निविदा विज्ञप्ति में दर्शाया गया है दिनांक 21.08.2026 से डाउनलोड किया जा सकता है एवं कार्यालयीन अवधि में कार्यालय में उपस्थित होकर देखी जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बालोद
जिला-बालोद (छ.ग.)

जी-262702928/6

खास खबर

रक्षा बंधन पर महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त जारी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 25 अगस्त को बालोद जिले के विकासखण्ड मुख्यालय डौण्डीलोहारा के लाल रघुवीर सिंह स्टेडियम में आयोजित बिहान दीदी एवं स्व-सहायता समूह के सम्मान समारोह के अवसर पर महतारी वंदन योजना के 31वीं किस्त 67 लाख 28 हजार 918 हितग्राहियों के खाते में 631 करोड़ 38 लाख 37 हजार 700 रूपये की राशि का अंतरण करेंगे। उल्लेखनीय है कि विष्णु भैय्या के द्वारा रक्षाबंधन के ठीक पूर्व महतारी वंदन योजना की राशि बहनों के खातें में सीधे अंतरण कर लाभान्वित करेंगे।प्रतिमाह मिलने वाली इस राशि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा सुपोषण के लिए अत्यंत मददगार साबित हो रहा है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 111 उप अभियंताओं की नियुक्ति

रायपुर। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 111 उप अभियंताओं की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इनमें 101 सिविल अभियंता और 10 विद्युत/यांत्रिक अभियंता शामिल हैं। प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा नियुक्ति के साथ ही सभी चयनित उप अभियंताओं की पदस्थापना के आदेश भी जारी किए गए हैं। चयनितों को नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर पदस्थापना कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने कहा गया है। निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी। पदस्थापना विकल्प के संबंध में कांउसलिंग के बाद उच्चतम न्यायालय में दायर स्थगन के कारण नियुक्ति प्रक्रिया विलंबित रही। उच्चतम न्यायालय द्वारा 20 अगस्त 2026 को याचिका के निराकरण के बाद 22 अगस्त को अनुशंसित चयन सूची के अनुसार सिविल के 101 उप अभियंताओं तथा विद्युत/यांत्रिकी के 10 उप अभियंताओं के पदस्थापना आदेश जारी कर दिए हैं।

अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत प्रतिभावान बच्चों को मिला अवसर

श्रमिक परिवारों के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा देकर उनके सपनों को पंख देना शासन की प्राथमिकता

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। श्रमिक हमारे विकास की मजबूत नींव हैं। अपने परिश्रम से वे सड़कें, भवन, पुल और विकास की अनेक संरचनाएं खड़ी करते हैं। ऐसे श्रमिक परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा और जीवन में आगे बढ़ने के समान अवसर देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। श्रमिक परिवारों के बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़ेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, तभी विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत का संकल्प भी साकार होगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।

समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने योजना के अंतर्गत अध्ययनरत बच्चों से आत्मीय संवाद किया और शिक्षा, खेल, कला तथा सह-शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत 1 लाख 45 हजार 841 श्रमिकों को 39 करोड़ 67 लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्रमिक परिवारों के बच्चों को आज व्यवस्थित यूनिफॉर्म में, आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी में संवाद करते और शिक्षा के साथ खेल तथा अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इन बच्चों का आत्मविश्वास इस बात का प्रमाण है कि उचित अवसर और अच्छी शिक्षा मिले तो कोई भी परिस्थिति प्रतिभा को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाना कभी श्रमिक परिवारों के लिए कठिन सपना हुआ करता था, आज राज्य सरकार उस सपने को साकार कर रही है। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना केवल बच्चों को अच्छे विद्यालयों में प्रवेश दिलाने की योजना नहीं है, बल्कि उन्हें बेहतर वातावरण, आत्मविश्वास और अपने सपनों को पूरा करने के लिए समान अवसर देने की पहल है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के साथ उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों से आत्मीय संवाद करते हुए अपने जीवन के संघर्ष और अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बच्चों से कहा कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, शिक्षा, परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे अभी से बड़े सपने देखें और तय करें कि भविष्य में किस क्षेत्र में जाकर देश और प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, वैज्ञानिक या प्रशासनिक अधिकारी, तो कोई व्यवसाय, समाजसेवा अथवा अन्य क्षेत्र में जाना चाहता है। लक्ष्य कोई भी हो, उसकी मजबूत नींव शिक्षा ही है। इसलिए बच्चों को मिले इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आज उच्च शिक्षा के लिए आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान उपलब्ध हैं। श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हेतु ऋण तथा विदेश में अध्ययन के लिए सहायता जैसी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। सरकार चाहती है कि आर्थिक परिस्थितियां किसी प्रतिभावान बच्चे की शिक्षा और उसके सपनों के रास्ते में बाधा न बनें।

100 से 200 हुई उत्कृष्ट विद्यालय में सीटें ; डीपीएस-आरपीएस जैसे स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे

उन्होंने कहा कि अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की शुरुआत पिछले वर्ष 100 बच्चों के साथ की गई थी। इस वर्ष इसका विस्तार करते हुए 200 बच्चों को योजना के अंतर्गत प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में शिक्षा का अवसर दिया गया है। प्रदेश के सभी 33 जिलों से चयनित प्रतिभावान बच्चे राजकुमार कॉलेज, दिल्ली पब्लिक स्कूल और रुंगटा पब्लिक स्कूल जैसे प्रतिष्ठित विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

श्रमिकों के परिश्रम से खड़ी होती है विकास की मजबूत बुनियाद, इन्हीं से बनेगा विकसित भारत

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश और देश के निर्माण में श्रमिकों के योगदान को नमन करते हुए कहा कि शहरों की ऊंची इमारतों से लेकर गांवों की सड़कों तक और बड़े पुलों से लेकर विकास की अनेक अधोसंरचनाओं के पीछे श्रमिकों का परिश्रम है। सरकार का दायित्व है कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कल ये ही बच्चे विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत की नींव रखेंगे।

3 मंडलों द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित की जा रही हैं 67 प्रकार की योजनाएं

उन्होंने कहा कि श्रम विभाग के तीन मंडलों के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण के लिए 67 प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृत्व सहायता, दिव्यांग सहायता, पेंशन, कौशल उन्नयन, रोजगार और आवास सहित जीवन के विभिन्न चरणों में सहायता देने वाली योजनाएं शामिल हैं। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इन योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पात्र श्रमिकों तक पहुंचे और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो।

दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना से सेवती और अंजू बनीं आत्मनिर्भर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में श्रम विभाग द्वारा संचालित दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना, महिलाओं के जीवन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की नई इबारत लिख रही है। बालोद जिले के ग्राम झलमला की सेवती ठाकुर और ग्राम सिवनी की अंजू नेताम इस योजना का लाभ लेकर न केवल आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का

स्रोत बन रही हैं। ग्राम झलमला निवासी सेवती ठाकुर श्रम विभाग में पंजीकृत हैं और स्व-सहायता समूह से जुड़कर कैंटीन का संचालन करती हैं। उन्होंने बताया कि पहले कैंटीन के लिए कच्चा माल और खाद्य सामग्रियां बाजार से लाने में काफी दिक्कतों और भारी किराये का सामना करना पड़ता था। दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत आर्थिक अनुदान और बैंक ऋण के सहयोग से उन्होंने ई-रिक्शा खरीदा। अब वे स्वयं परिवहन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, जिससे प्रतिदिन के किराये की बचत हो रही है और समूह के मुनाफे में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। सेवती ठाकुर कहती हैं कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय हम महिलाओं के लिए बड़े भाई की तरह संबल बनकर खड़े हैं। इस मदद के लिए हम अपने विष्णु भैया का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ग्राम सिवनी की श्रीमती अंजू नेताम पहले एक सामान्य गृहिणी थीं।

योजना के तहत ई-रिक्शा मिलने के बाद उन्होंने इसे स्वरोजगार का जरिया बनाया। अब वे गांव के स्कूली बच्चों को घर से स्कूल पहुंचाने और ले आने के साथ अन्य स्थानीय परिवहन सेवाएं देती हैं। इस कार्य से उन्हें प्रतिमाह लगभग 10 से 12 हजार रुपए की शुद्ध आमदनी हो रही है, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। अंजू ने बताया कि उन्हें महतारी वंदन योजना का भी नियमित लाभ मिल रहा है।

चिंतावागु नदी बनी चुनौती तो नगर सेना बनी सहारा, नाव से लगाया ग्रामीणों को पार

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में उफनती चिंतावागु नदी के तेज बहाव और बढ़े हुए जलस्तर के बीच नगर सेना की बचाव टीम ने गुड्डीपाल गांव की एक बीमार महिला विमला अंगनपल्ली और उनके परिजनों को सुरक्षित नदी पार कराकर बीजापुर जिला अस्पताल पहुंचाया और जीवन बचाया।

बीजापुर जिले में लगातार बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित होने पर जिला प्रशासन और राहत-बचाव दल पूरी तत्परता से ग्रामीणों की मदद में जुटे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल और वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में प्रशासन द्वारा विषम परिस्थितियों में ग्रामीणों को सुरक्षित आवागमन और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में तहसील बीजापुर के ग्राम चिन्नाकवाली के पास चिंतावागु नदी में पानी का बहाव बढ़ने से नदी पार करना ग्रामीणों के लिए मुश्किल हो गया। नगर सेना की टीम ने मौके पर पहुंचकर बोट के माध्यम से ग्रामीणों को सुरक्षित नदी पार कराया।

चिंतावागु नदी में तेज बहाव के बीच नगर सेना के जवानों ने पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ बोट का संचालन किया। टीम ने विशेष रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें सुरक्षित नदी के दूसरे छोर तक पहुंचाया। इससे ग्रामीणों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं और उपचार तक पहुंचने में मदद मिली। नगर सेना के जवानों की तत्परता और सेवा भावना से बारिश के बीच ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली।

बारिश के मौसम में नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने से दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित होता है। जिला प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव दलों को सक्रिय रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर ग्रामीणों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

वित्त मंत्री ने किया अरुण जेटली का पुण्यस्मरण

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री, वरिष्ठ राजनेता एवं पद्म विभूषण से सम्मानित अरुण जेटली जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री चौधरी ने कहा कि श्री जेटली एक कुशल प्रशासक, प्रखर वक्ता, उत्कृष्ट विधिवेत्ता और दूरदर्शी राजनेता थे। उन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रहित और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में श्री अरुण जेटली जी ने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और वित्तीय व्यवस्था में व्यापक सुधारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्तु एवं सेवा कर जैसे ऐतिहासिक आर्थिक सुधार को लागू करने में उनके नेतृत्व और योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। पूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली की नीति-निर्माण क्षमता, आर्थिक विषयों की गहरी समझ और राष्ट्र के प्रति समर्पण उन्हें विशिष्ट बनाता था।

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को समर्पित है सरकार

तर्रीघाट हाई स्कूल पहुंचे शिक्षा मंत्री गजेन्द्र विद्यार्थियों से किया संवाद, दी जरूरी हिदायतें

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने पाटन विकासखंड अंतर्गत ग्राम तर्रीघाट स्थित शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर का जायजा लिया तथा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से संवाद कर स्कूल में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यार्थियों की उपस्थिति, पाठ्यक्रम की प्रगति एवं विद्यालय की आवश्यकताओं की जानकारी ली।

शिक्षा मंत्री श्री यादव ने विद्यार्थियों से सीधे संवाद करते हुए उनकी पढ़ाई, रुचि, पसंदीदा विषय, पढ़ाई में आने वाली कठिनाइयों तथा भविष्य के लक्ष्यों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने, अनुशासन का पालन करने और मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मजबूत एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है।

उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि नियमित अध्ययन, अनुशासन और निरंतर मेहनत के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी अपने सपनों को साकार कर सकता है।

विद्यालय निरीक्षण के दौरान शिक्षा मंत्री श्री यादव ने शिक्षकों को बच्चों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने, पाठ्यक्रम को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने तथा विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति पर निरंतर निगरानी रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद, सांस्कृतिक एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी भी बढ़ाई जाए, ताकि बच्चों का सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास सुनिश्चित हो सके।

विद्यालय भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव से खुलकर संवाद किया और विद्यालय से जुड़ी अपनी आवश्यकताओं एवं समस्याओं से अवगत कराया। विद्यार्थियों ने प्रार्थना स्थल पर डोमशेड निर्माण तथा विज्ञान कक्षा के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने की मांग रखी।

शासकीय योजाओं से हो रहा महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

नमो ड्रोन दीदी योजना से चित्ररेखा के सपनों को मिली उड़ान

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। नमो ड्रोन दीदी योजना ने बालोद जिले की चित्ररेखा साहू के जीवन में बदलाव की नई कहानी लिखी है। कभी घर-परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित रहने वाली चित्ररेखा आज आधुनिक कृषि तकनीक की जानकार बनकर किसानों के खेतों में ड्रोन से नैनो उर्वरकों के छिड़काव का कार्य कर रही हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ उन्हें एक नई सामाजिक पहचान भी मिली है। आज लोग उन्हें सम्मानपूर्वक 'ड्रोन दीदी' के नाम से जानते हैं।

चित्ररेखा साहू बताती हैं कि ड्रोन दीदी बनना उनके लिए केवल रोजगार का अवसर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत है। आधुनिक कृषि यंत्र ड्रोन के माध्यम से किसानों के खेतों में नैनो उर्वरकों का छिड़काव कर वे कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा रही हैं। उनके लिए यह अनुभव गर्व का विषय है कि अब वे किसानों की मदद करने के साथ-साथ स्वयं भी आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं।

ड्रोन दीदी के रूप में काम शुरू करने के बाद चित्ररेखा की आय में सुधार हुआ। आर्थिक स्थिति बेहतर होने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने लिए स्कूटी खरीदी, जिससे उनकी आवाजाही आसान हुई और काम के प्रति आत्मविश्वास बढ़ा। इसके बाद उन्होंने अपने घर का निर्माण कार्य पूरा कराया। अब वे अपनी बेटी को बेहतर शिक्षा दिलाने और उसके उज्ज्वल भविष्य को संवारने के लिए भी आर्थिक रूप से सक्षम हैं।

चित्ररेखा साहू कहती हैं कि ड्रोन दीदी बनने के बाद उन्हें सबसे बड़ी उपलब्धि अपनी नई पहचान के रूप में मिली है। अब गांव और आसपास के क्षेत्र में लोग उन्हें उनके नाम के साथ-साथ 'ड्रोन दीदी' के रूप में भी पहचानते हैं। यह पहचान उनके लिए सम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गई है। उनका कहना है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाएं उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

चित्ररेखा साहू ने महतारी वंदन योजना का भी उल्लेख करते हुए कहा कि योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता महिलाओं की रोजमर्रा की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में सहारा देती है। उनके अनुसार, एक ओर ड्रोन दीदी योजना ने उन्हें आय और रोजगार का अवसर दिया है, वहीं महतारी वंदन योजना जैसी पहल महिलाओं को नियमित आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। उनका मानना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाली ऐसी योजनाएं परिवार की खुशहाली और महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

चित्ररेखा ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री विष्णु भैया, हम महिलाओं के हित में निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि शासन की योजनाओं से महिलाओं को आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने के अवसर मिल रहे हैं।

सड़क हादसे में घायल जवानों का वन मंत्री केदार ने पूछा हाल, दिए जरूरी निर्देश

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। वन मंत्री केदार कश्यप ने जगदलपुर के डिमरापाल स्थित कॉन्टिनेंटल अस्पताल पहुंचकर सड़क दुर्घटना में घायल जवानों से मुलाकात की। उन्होंने जवानों के स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी ली तथा उनके परिजनों से भी चर्चा कर हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

वन मंत्री श्री कश्यप ने चिकित्सकों से जवानों की स्वास्थ्य स्थिति और उपचार की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अनुरूप साहू तथा कॉन्टिनेंटल अस्पताल के एजीएम डॉ. संतोष कुमार सिंह से चर्चा कर घायल जवानों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जवानों से मुलाकात के बाद वन मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि सभी घायल जवान कुशल हैं और उनका उपचार जारी है। उन्होंने चिकित्सकों को उपचार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखने तथा जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

गौरतलब है कि 23 अगस्त को वन मंत्री श्री केदार कश्यप ग्राम फरसागुड़ा, भानपुरी से कोंडागांव में आयोजित कार्यक्रम के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान भानपुरी थाना क्षेत्र में कोंडागांव की ओर से आ रही एक स्कॉर्पियो पायलट वाहन को पार करते समय वन मंत्री श्री कश्यप के वाहन के मिरर से टकरा गई। इसके बाद स्कॉर्पियो स्पेयर वाहन और फिर फॉलो वाहन से जा भिड़ी। दुर्घटना में फॉलो वाहन में सवार चालक और पुलिस जवान घायल हो गए। घटना के तत्काल बाद मंत्री श्री कश्यप ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था कराई और उनके उपचार की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की। गंभीर रूप से घायल जवानों को जगदलपुर रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप का घायल जवानों से अस्पताल पहुंचकर मिलना शासन की संवेदनशीलता और अपने सुरक्षा कर्मियों के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950